लखनऊ

बुधवार, 12 अगस्त , 2026

वर्ष : 11 । अंक: 343

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

महानता कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है।

TODAY WEATHER

DAY 32° Hi

NIGHT 28° Low

संक्षेप

राहुल गांधी देशद्रोही शक्तियों के हाथ आ चुके हैं, कंगना रनौत का कांग्रेस नेता पर वार

नई दिल्ली, एजेंसी। कंगना रनौत ने संसद के बाहर NDA के दूसरे सांसदों के साथ विरोध मार्च में शामिल होकर राहुल गांधी की आलोचना की। यह मार्च संसद लाइब्रेरी से मकर द्वार की ओर निकाला गया। इस एक्टर-नेता ने विपक्ष पर बार-बार संसद की कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप लगाया और विपक्ष के नेता से उठाए जा रहे मुद्दों पर जवाब देने को कहा। न्यूज़ एजेंसी ANI से बात करते हुए कंगना ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने इस मुद्दे पर बहस की मांग करने के बावजूद इस मामले पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। कंगना ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर बात करने से इनकार कर दिया है। पहले उन्होंने कहा था कि वे कॉकरोच वाले विरोध प्रदर्शन पर बात करना चाहते हैं। लेकिन जब उनका स्वागत किया गया, तो उन्होंने इस मुद्दे पर बात करने से मना कर दिया। उन्होंने विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आप देख सकते हैं कि वे आपके देश को कितना धोखा दे रहे हैं। वे संसद को एक दिन भी नहीं चलने दे रहे हैं। कंगना ने कहा कि पहले तो उन्होंने (विपक्ष ने) चर्चा कराने के लिए इतना हंगामा किया। अब जब चर्चा होने जा रही है, तो वे उससे भाग रहे हैं। वे अमित शाह जी की बात नहीं सुनना चाहते। ऐसे में सदन कैसे चलेगा? देश देख रहा है कि वे किस तरह देश-विरोधी ताकतों के हाथों में पड़ गए हैं। यह शर्म की बात है कि उन्होंने इस दौरान सदन को एक दिन भी नहीं चलने दिया। विरोध मार्च के दौरान, कंगना को एक तख्ती पकड़े हुए देखा गया, जिस पर लिखा था, झारखंड में छात्रों पर हुई हिंसा पर राहुल गांधी जवाब दो! एनडीए सांसदों ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए नारे भी लगाए, जिनमें 'राहुल गांधी जवाब दो' और 'राहुल गांधी भागो मत' शामिल हैं।

एयर इंडिया की फ्लाइट में टर्बुलेंस के पीछे खुली तकनीकी खामियों की पोल, फ्रांस की टीमें भारत पहुंचकर करेंगी जांच

नई दिल्ली। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में सफर कर रहे यात्रियों के लिए 4 अगस्त का दिन किसी भयानक सपने से कम नहीं था। इस उड़ान के दौरान हुए गंभीर टर्बुलेंस (हवा के तेज झटके) मामले में अब एक के बाद एक कई रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे हो रहे हैं। पहले एक पायलट के नशे में होने (डोप टेस्ट फेल) की सनसनीखेज खबर सामने आई और अब इस घटना में बड़ी तकनीकी खामियों की भी पुष्टि हुई है, जिसने हवा में सैकड़ों यात्रियों की जान सांसत में डाल दी थी। इस खौफनाक सफर के दौरान विमान ए-320 में तीन छोटे बच्चों समेत कुल 137 यात्री और 8 क्रू मेंबर्स सवार थे। यात्रा के दौरान विमान को करीब पांच मिनट तक हवा के भीषण झटकों का सामना करना पड़ा और वह आसमान में अचानक 300 फीट नीचे आ गिरा। झटके इतने तेज थे कि केबिन के अंदर चीख-पुकार मच गई और एक छोटा बच्चा विमान के पिछले हिस्से की तरफ उछल गया। इस जानलेवा घटना में 13 यात्रियों और चालक दल के चार सदस्यों सहित कुल 17 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ताजा रिपोर्ट के अनुसार, इस घटना के पीछे केवल मौसम ही नहीं, बल्कि गंभीर तकनीकी खामियां भी जिम्मेदार थीं।

पीएम मोदी का नया इंस्टा वीडियो

15 अगस्त के लिए देशवासियों से की अपील; बोले- हर घर तिरंगा को बनाएं उत्सव

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक नया वीडियो संदेश साझा किया है। इसमें उन्होंने देशवासियों से 'हर घर तिरंगा' अभियान को हर घर में उत्सव के रूप में मनाने की अपील की। पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा 'आइए, हर घर तिरंगा को हर घर में एक उत्सव बनाएं।' यह संदेश 15 अगस्त को होने वाले 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आया है। इस मौके पर देश आजादी की 80वीं वर्षगांठ मनाएगा।

अपने वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से 15 अगस्त को गर्व और सम्मान के साथ मनाने की अपील की। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को श्रद्धांजलि देने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने की बात कही। पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा 'हर घर में तिरंगा, हर घर में तिरंगा, हर दिल में तिरंगा। आइए, हम हर घर में तिरंगा फहराएं।'

'हर घर तिरंगा' अभियान पूरे अगस्त महीने में चलाया जा रहा है। इसके तहत लोगों को अपने घरों, दुकानों, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

अभियान का उद्देश्य केवल तिरंगा फहराने तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों के भीतर राष्ट्रीय ध्वज के प्रति गर्व और जुड़ाव की भावना को मजबूत करना भी है। सरकार और विभिन्न संगठनों की ओर से देशभर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें लोग सामूहिक रूप से तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस के उत्सव में शामिल हो रहे हैं।

'हर घर तिरंगा' अभियान की शुरुआत आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान हुई थी। इसके बाद से हर साल स्वतंत्रता दिवस से पहले इस अभियान को उत्साह के साथ मनाया जाता है। 2026 में भी अभियान के तहत परिवारों को अपने घर की बालकनी, छत या मुख्य द्वार पर तिरंगा लगाने और पड़ोसियों के साथ मिलकर स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

सांसद जी आज भाषण नहीं दिए, लगता है दावत... सीएम योगी ने रविकिशन पर ली चुटकी

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के सांसद और भोजपुरी स्टार रवि किशन पर मज़ाकिया अंदाज़ में तंज कसा। उन्होंने कहा कि बेहतर हवाई कनेक्टिविटी की वजह से अब कोई यह पता नहीं लगा सकता कि किशन किसी खास दिन गोरखपुर, मुंबई या दिल्ली में हैं। उनकी इस बात पर ज़ोरदार ठहाके लगे। गोरखपुर में बेहतर हवाई कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हुए योगी ने कहा कि कनेक्टिविटी में ज़बरदस्त बदलाव आया है। एक दशक पहले जहाँ दिन में सिर्फ़ एक फ़्लाइट चलती थी, वहीं अब शहर से 14 फ़्लाइट्स चल रही हैं। इसके बाद उन्होंने दर्शकों के बीच बैठे किशन की ओर ध्यान दिया मैं रवि किशन के बारे में हमेशा यही कहता हूँ। कोई नहीं बता सकता कि वह कब गोरखपुर में हैं और कब मुंबई में। अगर वह मुंबई में नाश्ता करते हैं, तो दोपहर का खाना गोरखपुर में खा लेते हैं। और यहाँ बस अपनी झलक दिखाने के बाद, वह दिल्ली भी चले जाते हैं।

योगी ने हँसी-मज़ाक के बीच कहा कि हवाई कनेक्टिविटी के बिना, ऐसा शेड्यूल बनाए रखना मुश्किल होता। इन बातों पर किशन और उनके आस-पास बैठे लोग ज़ोर-ज़ोर से हँसते हुए दिखे। 70 करोड़ रुपये की लागत से बनी 1.80 किलोमीटर लंबी 'ग्रीन सिटी रोड' (जो नेशनल हाईवे-24 को पटनिया होते हुए माधोपुर बांधा से जोड़ती है) के उद्घाटन के दौरान, योगी ने किशन पर फिर से चुटकी ली। उन्होंने कहा कि उस दिन सांसद ने कोई भाषण नहीं दिया। पता नहीं रवि किशन जी ने आज भाषण क्यों नहीं दिया।

अभिजीत दिपके का सरकारों से सवाल

राजनीतिक पार्टियों पर क्यों नहीं आंसू गैस, छात्रों पर जुल्म क्यों

नई दिल्ली, एजेंसी। मंगलवार को 'कॉकरोच जनता पार्टी' के फाउंडर अभिजीत दिपके ने झारखंड पब्लिक सर्विस एग्ज़ाम में गड़बड़ियों को लेकर हो रहे विरोध-प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे स्टूडेंट लीडर देवेंद्र नाथ महतो को प्रेरणा की आवाज़ बताया। दिपके ने महतो से फ़ोन पर बात की। महतो कई दिनों से भूख हड़ताल पर होने के बावजूद सोमवार को झारखंड विधानसभा तक निकाले गए मार्च में शामिल हुए थे। महतो ने सोमवार रात X (पहले ट्विटर) पर लिखा कि देर रात हमारी बातचीत CJP के फाउंडर अभिजीत दिपके से हुई। उन्होंने हमसे बात की, हमारी सेहत के बारे में पूछा और अपना पूरा समर्थन देने की बात कही। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दिपके ने कहा कि जब राजनीतिक पार्टियां विरोध-प्रदर्शन करती हैं, तो आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? सिर्फ़ छात्रों के ख़िलाफ़ ही इसका इस्तेमाल क्यों हो रहा है? मैंने देवेंद्र महतो से बात की, जिन्होंने मुझे बताया कि पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, जबकि वे पिछले नौ दिनों से भूख हड़ताल पर थे। देश की सभी सरकारों को सोचना चाहिए कि छात्रों पर ज़ुल्म करके उन्हें क्या हासिल हो रहा है। ऐसी बर्बरता नहीं होनी चाहिए। हमने देवेंद्र महतो को अपना समर्थन देने का भरोसा दिलाया। झारखंड में हमारी टीम छात्रों के साथ मिलकर काम कर रही है। छात्र आंदोलनों के बीच यह एकजुटता ऐसे समय में देखने को मिल रही है जब सत्ताधारी BJP ने झारखंड में JMM के नेतृत्व वाली सरकार (जिसमें कांग्रेस भी गठबंधन सहयोगी है) के खिलाफ़ आक्रामक रुख अपना लिया है।

'अपने रुख से पीछे नहीं हटेगा विपक्ष': तीन मांगों पर खरगे ने सरकार को घेरा, प्रियंका गांधी क्या बोलीं?

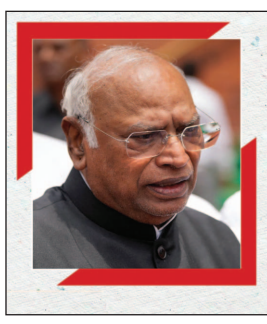

> मुद्दा छात्रों पर लाठीचार्ज और गोलीबारी का है। हम जानना चाहते हैं कि आदेश किसने दिया और यह कैसे हुआ। हम इस पर सदन में बयान चाहते हैं।
>
> *मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस अध्यक्ष*

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को कहा कि विपक्ष अपने रुख से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने तीन प्रमुख मुद्दे गिनाए। इनमें 20 जुलाई को छात्रों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई, राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी का मामला और इन मुद्दों पर सरकार से माफी की मांग शामिल है।

उन्होंने कहा कि जब तक इन मुद्दों का समाधान नहीं होता, तब तक विपक्ष इन्हें उठाता रहेगा। खरगे ने सरकार पर संसद में बयान देने से बचने का आरोप लगाया। मीडिया से बातचीत में खरगे ने कहा, हम अपना रुख नहीं बदल रहे हैं। शुरुआत से ही हमारा रुख एक जैसा रहा है और हमारे तीन स्पष्ट मुद्दे हैं।

छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर क्या कहा?

छात्रों पर हुई कथित ज्यादती को लेकर उन्होंने कहा, पहला मुद्दा छात्रों पर लाठीचार्ज और गोलीबारी का है। हम जानना चाहते हैं कि आदेश किसने दिया और यह कैसे हुआ। हम इस पर सदन में बयान चाहते हैं। खरगे ने आगे कहा, लाठीचार्ज के कारण कई छात्र बीमार पड़ गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 100 से ज्यादा छात्र घायल हुए। कई छात्रों को पैलेट गन से चोट लगी। हम इस मामले पर भी बयान चाहते हैं। 18 दिन हो चुके हैं और बयान देने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। वे सिर्फ जल्दी से एक टिप्पणी करके आगे बढ़ना चाहते हैं। उनका इरादा यही है।

तीन मांगों पर अड़ा विपक्ष

अन्य मांगों को गिनाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, दूसरा मुद्दा 'चढ़ावा चोरी' का है और तीसरा सरकार से माफी की मांग है। ये तीनों मुद्दे शुरुआत से हैं। ये अभी भी अहम हैं और जब तक इनका समाधान नहीं होता, तब तक बने रहेंगे। झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन और इंडिया ब्लॉक के भीतर दोहरे मापदंड के आरोपों पर खरगे ने कहा, यह अलग मुद्दा है। अगर सैकड़ों मुद्दे हैं, तो क्या उन सभी पर एक साथ चर्चा होगी? क्या हम हर एक मुद्दा उसी दिन उठाएंगे?

एनडीए सांसदों के प्रदर्शन के बीच क्या बोलीं प्रियंका गांधी?

वहीं, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मुलाकात की है। संसद में छात्र आंदोलन को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव जारी है। प्रियंका गांधी ने ये बातें एनडीए सांसदों के विरोध प्रदर्शन के बीच संसद पहुंचने के बाद कहीं। एनडीए सांसदों ने विपक्ष पर सदन में चर्चा से भागने का आरोप लगाया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, राहुल गांधी ने झारखंड के छात्रों से मुलाकात की है। उन्होंने संसद परिसर में सत्तारूढ़ दल के सांसदों के विरोध प्रदर्शन पर भी निशाना साधा। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में आकर बयान देने की मांग की। प्रियंका गांधी ने कहा, मैंने पहली बार देखा है कि सत्तारूढ़ दल के सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कम से कम हमने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर तो किया है।

जनहित के मुद्दों से ध्यान भटका रही बीजेपी-कांग्रेस, मायावती ने बताया सोची-समझी कंस्पायरेसी

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। बसपा प्रमुख मायावती ने मंगलवार को बीजेपी और विपक्षी पार्टियों की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि ये पार्टियां मॉनसून सत्र के दौरान संसद की कार्यवाही में बाधा डाल रही हैं ताकि केंद्र और राज्य सरकारों की कमियों से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में BSP प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी देश के युवाओं, यानी 'जेन Z' के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि उनका विरोध सीधे तौर पर छात्रों और उनके माता-पिता की समस्याओं से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि BSP इन मुद्दों का समाधान खोजने की पूरी कोशिश कर रही है।

BSP प्रमुख मायावती ने कहा जैसा कि सभी जानते हैं, कुछ समय से सत्ता पक्ष और विपक्ष (BJP, कांग्रेस और अन्य) किसी न किसी मुद्दे पर संसद में बाधा डाल रहे हैं और जनहित के अहम मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। हो सकता है कि केंद्र और राज्यों में अपनी सरकारों की कमियों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए उनके बीच कोई अंदरूनी समझौता हो, या फिर इन मुद्दों पर बात करने से बचने के लिए कोई साजिश हो। देश के लोग साफ देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। अब देश के युवा, यानी 'जेन Z', अपनी कई समस्याओं को लेकर बहुत परेशान और चिंतित हैं। BSP हमेशा से अपनी राजनीतिक सोच के तहत उनके साथ खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। उनका विरोध छात्रों और उनके माता-पिता की समस्याओं से जुड़ा है। BSP इसका समाधान खोजने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। मायावती का यह बयान तब आया जब आज संसद परिसर में विपक्षी सांसदों - जिनमें कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव और डिंपल यादव शामिल थे - ने अयोध्या में राम मंदिर में दान में कथित चोरी और हेराफेरी तथा झारखंड में विरोध कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष श्री राम जन्मभूमि मंदिर को दिए गए दान में कथित अनियमितताओं पर संसद में चर्चा की मांग कर रहा है और साथ ही हालिया विरोध प्रदर्शनों के दौरान छात्रों के साथ किए गए व्यवहार पर सरकार से जवाब भी मांग रहा है।

वंदे मातरम की अनिवार्यता पर शशि थरूर को होने लगी चिंता, बोले- नतीजा उलटा न हो जाए

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' को पूरा गाने की नई ज़रूरत की व्यावहारिकता पर सवाल उठाए हैं। उनका तर्क है कि कई देशभक्ति गीतों को पूरा गाने में लगने वाला लंबा समय दर्शकों के धैर्य की परीक्षा ले सकता है। थरूर की यह टिप्पणी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 'राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026' को मंज़ूरी दिए जाने के बाद आई है। इस विधेयक के तहत 'वंदे मातरम' को भी राष्ट्रगान की तरह ही कानूनी सुरक्षा मिल गई है।

संसद के मॉनसून सत्र के दौरान इस संशोधन को मंज़ूरी दी गई थी; राज्यसभा ने इसे 29 जुलाई को और लोकसभा ने अगले दिन पारित किया था। इस कानून में राष्ट्रीय गीत को जानबूझकर गाने से रोकने या इसे गाते समय किसी सभा में बाधा डालने पर सज़ा का प्रावधान है, जिसमें तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों शामिल हो सकते हैं। X पर एक पोस्ट में, थरूर ने कहा कि वह 'वंदे मातरम' और 'जन गण मन' दोनों का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन नए प्रोटोकॉल के लिए ज़रूरी समय को लेकर उन्होंने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने Vande Mataram संशोधन को मंज़ूरी दे दी है। संसद में बिना किसी चर्चा के पारित हुए इस संशोधन के तहत, किसी भी सरकारी कार्यक्रम की शुरुआत और समापन पर राष्ट्रगान के अलावा राष्ट्रगीत को भी पूरा गाना ज़रूरी है। थरूर ने कहा कि वह 'वंदे मातरम' के शुरुआती हिस्से से तो परिचित हैं, लेकिन इसके सभी छंदों से नहीं; उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी कार्यक्रमों में पहले अतिरिक्त छंदों को गाने की कोई अनिवार्यता नहीं थी।

भाजपा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा- डरें नहीं, संसद में गृह मंत्री का भाषण सुनें

नई दिल्ली, एजेंसी। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने संसद में जारी विपक्ष के हंगामे पर राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की हमेशा से आदत रही है कि वो सदन में जवाब नहीं सुनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह हर विषय पर जवाब देने को तैयार हैं लेकिन कांग्रेस, इससे भाग रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि वो सदन में चर्चा से भागती है। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा सांसद ने दावा किया और राहुल गांधी को चुनौती दी है कि गृह मंत्री सदन में आकर बिंदुवार जवाब देने को तैयार हैं, इसीलिए सदन छोड़कर आप न भागे।

रांची में छात्रों के आंदोलन का जिक्र करते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि रांची में अनुशासित, मर्यादित छात्र जो पूर्णतः गैर राजनीतिक, सामान्य, समुचित मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है वह अनुचित है। राहुल गांधी के कान पूरी तरह से बंद हैं। रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है। सत्र के दौरान सदन से भागते हैं और सत्र के बाद विदेश भागते हैं। यह स्वाभाविक है कि इस बार भी वे सत्र के बाद विदेश भागेंगे, लेकिन इससे पहले इतनी हिम्मत जुटाइए, इतना साहस जुटाइए और गृह मंत्री का वक्तव्य सुनकर जाइए।

पूर्व के विपक्ष के नेता का दिया उदाहरण

उन्होंने विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी का जिक्र करते हुए कहा कि जब खरगे जैसे सीनियर नेताओं ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता का पद संभाला और इससे पहले जब अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में विपक्ष के नेता थे, तब भी ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी गई। उस समय के बारे में सोचिए जब अरुण जेटली विपक्ष के नेता थे या अटल जी की सरकार के दौरान जब सोनिया गांधी और डॉ. मनमोहन सिंह विपक्ष में थे। क्या ऐसा नजारा पहले कभी देखा गया था।

भाजपा सांसद ने पुरानी घटनाओं का किया जिक्र

इससे पूर्व भी सदन में ऐसे कई अवसर रहे हैं, जब किसी विधेयक पर अंतिम जवाब दिया जाता है तो कांग्रेस पार्टी भाग खड़ी होती है। अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी का जवाब नहीं सुना, भाग खड़े हुए। मणिपुर पर पीएम मोदी का जवाब नहीं सुना, भाग खड़े हुए। अब मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं, गृह मंत्री सदन में आकर बिंदुवार जवाब देने को तैयार हैं, आप सदन से भागिए मत।

अपने आखिरी दौर में संसद का मानसून सत्र

भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि संसद का मानसून सत्र अपने आखिरी दौर में है। इस सत्र के बाद भारत अपनी आजादी के 80वें साल में प्रवेश करेगा। हालांकि इस सत्र के दौरान सदन में जो कुछ भी हो रहा है, वह निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती बनकर उभर रहा है। मेरा मानना है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि कोई व्यक्ति, जो अहंकार और मनमानी के कारण किसी बिगड़े हुए राजकुमार की तरह व्यवहार करता हो, देश के सर्वोच्च सदन को बंधक बना लेगा। हमें ऐसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा है कि विपक्ष, खासकर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने व्यवहार से लगातार यह दिखाया है कि वे सदन में कोई सार्थक चर्चा नहीं होने देना चाहते। उन्होंने लगातार अपनी मांगें बदली हैं।

'संसद को काम क्यों नहीं करने दे रहे हैं?'

पहले, उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा से जुड़े नियमों में बदलाव किए जाने चाहिए, और उस मांग को मान लिया गया। उन्होंने कड़े कानूनों की मांग की, जैसा कि छात्रों ने चाहा था, और उसे भी स्वीकार कर लिया गया। कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी और एक नया बिल भी पेश किया गया। उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। उसे मान लिया गया। उन्होंने मांग की कि छात्रों से जुड़े केस वापिस लिए लिए जाएं। उसे भी मान लिया गया। फिर मांग की कि गृह मंत्री सदन में आएं और बयान दें। उस मांग को भी मान लिया गया। अब जब गृह मंत्री सदन में आकर जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो वे संसद को काम क्यों नहीं करने दे रहे हैं।

मिट्टी के कारोबार पर 'कब्जे' की मार, दम तोड़ रही कुम्हारी कला

प्लास्टिक-कागज ने छीना बाजार, मिट्टी के स्रोतों ने छोड़ा साथ

» पुश्तैनी हुनर छोड़ पलायन कर रहे कुम्हारों के युवा

आर्यावर्त संवाददाता

बल्दीराय/सुल्तानपुर। जिस मिट्टी से कभी गांवों की रसोई सजती थी, उसी मिट्टी का कारोबार आज दम तोड़ता नजर आ रहा है। घड़ा, सुराही, कुल्हड़, दीया और मिट्टी के अन्य बर्तन बनाने वाली सदियों पुरानी कुम्हारी कला बाजार की बदलती तस्वीर के साथ-साथ सरकारी उदासीनता की भी शिकार होती दिखाई दे रही है। एक ओर प्लास्टिक और कागज के उत्पादों ने कुम्हारों का बाजार छीना, वहीं दूसरी ओर कुम्हारी कार्य के लिए उपयोगी तालाब और मिट्टी के स्रोत लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं।

दिलचस्प यह है कि प्रदेश में कुम्हारी कला के लिए उपयुक्त चिकनी मिट्टी उपलब्ध कराने की सरकारी व्यवस्था पहले से मौजूद है। शासनादेश के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर ऐसे ताल, पोखर अथवा अन्य स्थलों को चिन्हित कर कुम्हारों को कुम्हारी कार्य के लिए मिट्टी निकालने हेतु पट्टा दिए जाने का प्रावधान है। लेकिन सवाल यह है कि जब कुम्हारों के लिए मिट्टी के स्रोत ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो सरकारी प्रावधान किस काम का ? ग्रामीण क्षेत्रों में कई कुम्हारी तालाबों की स्थिति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कहीं तालाब सिकुड़ गए हैं, कहीं उनका स्वरूप बदल गया है और कहीं कथित तौर पर दूसरे लोगों के कब्जे की शिकायतें सामने आती हैं। ऐसे में कुम्हारों को अपने पुश्तैनी कारोबार के लिए मिट्टी जुटाना भी मुश्किल हो रहा है।

राजस्व अभिलेख बनाम मौके की हकीकत

सबसे बड़ा सवाल राजस्व विभाग की भूमिका को लेकर है। यदि किसी तालाब अथवा भूमि का उपयोग कुम्हारों के लिए निर्धारित है, तो उसका राजस्व रिकॉर्ड क्या कहता है ? मौके पर उसका वास्तविक रकबा कितना बचा है ? उस पर किसका कब्जा है? क्या कभी उसका सीमांकन और सत्यापन कराया गया? यही वे सवाल हैं जिनका जवाब प्रशासनिक स्तर पर तलाशा जाना जरूरी है। क्योंकि प्रदेश में तालाबों पर अवैध कब्जे की शिकायतें नई नहीं हैं। हाल में संभल में प्रशासन ने तालाब और झील की भूमि से बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई की है। बल्दीराय क्षेत्र में भी कुम्हारी तालाबों की ग्रामवार स्थिति, राजस्व अभिलेख और मौके की स्थिति का मिलान कराया जाए तो तस्वीर सामने आ सकती है कि कितने तालाब वास्तव में कुम्हारों के उपयोग में हैं और कितने सिर्फ कागजों में दर्ज हैं।

तालाब खत्म, कारोबार खत्म और फिर शुरू होता है पलायन

कुम्हारी कला केवल मिट्टी के बर्तन बनाने का काम नहीं, बल्कि ग्रामीण स्वरोजगार की परंपरा भी रही है। लेकिन बढ़ती लागत, मिट्टी की अनुपलब्धता और बाजार में प्लास्टिक-कागज के सस्ते विकल्पों ने कुम्हार परिवारों की आय को प्रभावित किया है। नतीजा यह है कि कुम्हार समुदाय के पढ़े-लिखे और युवा वर्ग का एक हिस्सा पुश्तैनी काम से दूरी बनाकर मजदूरी अथवा दूसरे रोजगार की तलाश में बाहर जाने को मजबूर है।

सरकार की मंशा पर नहीं, अमल पर सवाल

सरकार यदि माटी कला को बचाने की बात करती है तो केवल योजनाएं और शासनादेश पर्याप्त नहीं होंगे। जरूरत है कि कुम्हारी तालाबों का सर्वे, सीमांकन, अवैध कब्जों की जांच और वास्तविक पात्र कुम्हार परिवारों को मिट्टी उपलब्ध कराने की व्यवस्था जमीन पर दिखाई दे। कुम्हार समुदाय की मांग है कि राजस्व विभाग प्रत्येक ग्राम पंचायत में कुम्हारी तालाबों की स्थिति स्पष्ट करे, कब्जों की शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराए और तालाबों को अतिक्रमण से मुक्त कराए। साथ ही मिट्टी के बर्तनों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण, उपकरण, बाजार और सरकारी खरीद जैसी व्यवस्थाओं को बढ़ावा दिया जाए। वरना खतरा सिर्फ तालाबों के मिटने का नहीं हैकुएक पूरी लोककला, उससे जुड़ा रोजगार और पीढ़ियों से चली आ रही मिट्टी की वह विरासत भी इतिहास के पन्नों में सिमट सकती है, जिसे बचाने की जिम्मेदारी आज भी शासन-प्रशासन की है।

जबरन घर में घुसकर महिला से अभद्रता का आरोप, पति से मारपीट कर मोबाइल छीना

आर्यावर्त संवाददाता

बल्दीराय/सुल्तानपुर। धनपतगंज थाना क्षेत्र के कुर्मी का पुरवा मजरे अगई गांव में महिला ने एक नामजद समेत तीन लोगों पर घर में घुसकर अभद्रता, मारपीट, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग और धमकी देने का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एफआईआर के अनुसार शिकायतकर्ता निशा देवी पत्नी उदय भान का आरोप है कि आलोक मिश्रा उर्फ खुशबू पुत्र राम कृष्ण मिश्रा उस पर कथित रूप से जबरन अवैध संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। विरोध करने पर फोन कर परेशान करने तथा अश्लील बातें करने का आरोप भी लगाया गया है। शिकायत में कहा गया है कि 24 जुलाई 2026 की रात आरोपी कथित तौर पर दो अज्ञात व्यक्तियों के साथ उसके घर पहुंचा और जबरन घर में घुसकर अभद्र हरकत व दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया। विरोध करने पर जातिसूचक शब्द कहने और गाली-गलौज करने का आरोप है। शोर सुनकर पहुंचे महिला के पति के साथ भी कथित मारपीट की गई तथा उनका मोबाइल छीन लिया गया। शिकायतकर्ता ने जान से मारने की धमकी मिलने की बात भी कही है।

धनपतगंज पुलिस ने 10 अगस्त 2026 को एफआईआर संख्या 0162 दर्ज की। मुकदमे में एससी/एसटी एक्ट की संबंधित धाराएं लगाई गई हैं। मामले की विवेचना सीओ बल्दीराय को सौंपी गई है। वाले विवादों के निस्तारण में भी मदद मिलेगी। राजस्व विभाग के इस कदम को ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि पैमाइश की प्रक्रिया को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

डीजे गाड़ी को ओवरटेक करने पर रामपुर–संभल के कांवड़ियों में भिड़ंत, जमकर चले लाठी–डंडे

आर्यावर्त संवाददाता

बिजनौर। बिजनौर के धामपुर में सोमवार देर शाम करीब 10 बजे कांवड़ियों के दो गुटों में विवाद हो गया। राजपूताना चौपले पर रामपुर और संभल जिले के कांवड़ियों के बीच डीजे की गाड़ी को ओवरटेक करने को लेकर कहासुनी शुरू हुई।

देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के कांवड़ियों में मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान लाठी-डंडे चलने से कई कांवड़ियों के चोटिल होने की जानकारी है।

राजपूताना चौपले पर मची अफरातफरी

मारपीट के कारण राजपूताना चौपले पर काफी देर तक अफरातफरी का माहौल बना रहा। बड़ी संख्या में कांवड़ियों की मौजूदगी के कारण स्थिति संभालने में पुलिस को भी

काफी मशक्कत करनी पड़ी। धामपुर में कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए राजपूताना चौपले पर पुलिस चौकी स्थापित की गई है। पुलिसकर्मी लगातार कांवड़ियों की आवाजाही और सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रख रहे हैं।

पुलिस ने हस्तक्षेप कर शांत कराया मामला

विवाद की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के बीच बीच-बचाव का प्रयास किया। कांवड़ियों की संख्या अधिक होने के कारण पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने में काफी मेहनत करनी पड़ी। काफी प्रयास के बाद पुलिस ने मामला शांत कराया। इसके बाद दोनों पक्षों के कांवड़ियों को उनके गंतव्य की ओर रवाना कर दिया गया।

जांच के निर्देश, रिपोर्ट मांगी

अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी धामपुर अमित किशोर श्रीवास्तव ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। उन्होंने प्रभारी निरीक्षक को पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट से अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। पुलिस विवाद के कारणों और घटना में शामिल कांवड़ियों के संबंध में जानकारी जुटा रही है। अधिकारियों का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार निगरानी कर रही है।

28वीं अन्तर्जनपदीय लखनऊ जोन एथलेटिक क्लस्टर प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। रिजर्व पुलिस लाइन, सुलतानपुर में सोमवार को 28वीं अन्तर्जनपदीय लखनऊ जोन एथलेटिक क्लस्टर प्रतियोगिता-2026 का भव्य उद्घाटन हुआ। प्रतियोगिता में लखनऊ जोन के विभिन्न जनपदों से आए महिला एवं पुरुष पुलिसकर्मी एथलेटिक्स एवं साइकिलिंग की विभिन्न स्पर्धाओं में प्रतिभाग कर रहे हैं।

प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक, पीटीएस सुलतानपुर ब्रजेश कुमार मिश्र रहे। समारोह में पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर चारु निगम तथा अपर पुलिस अधीक्षक वृजनारायण सिंह सहित पुलिस विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस बल में शारीरिक दक्षता के साथ टीम भावना, आत्मविश्वास और अनुशासन का विशेष महत्व है। खेल प्रतियोगिताएं पुलिसकर्मियों को अपनी शारीरिक क्षमता एवं खेल प्रतिभा को निखारने का अवसर प्रदान करती हैं। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से खेल भावना के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का आह्वान किया। प्रतियोगिता में शामिल महिला एवं पुरुष पुलिसकर्मी विभिन्न एथलेटिक्स और साइकिलिंग स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। आयोजन के दौरान खिलाड़ियों ने अनुशासन एवं खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने का संकल्प लिया। सुलतानपुर पुलिस की ओर से प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों एवं टीमों को शुभकामनाएं दी गईं।

अवैध कच्ची शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई, 38 लीटर शराब बरामद

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। आबकारी आयुक्त के आदेश पर चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत मंगलवार को सुल्तानपुर में आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया। जिलाधिकारी सुल्तानपुर एवं उप आबकारी आयुक्त, अयोध्या प्रभार के निर्देश तथा जिला आबकारी अधिकारी सुल्तानपुर के निर्देशन में आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-1 रण विजय सिंह एवं आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-4 अरुण कुमार ने मय स्टाफ विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई की। अभियान के दौरान ग्राम बल्लीपुर में चौपाल लगाकर ग्रामीणों को अवैध शराब के सेवन से होने वाली जनहानि एवं स्वास्थ्य संबंधी नुकसान के प्रति जागरूक किया गया। इसके बाद ग्राम कमनगढ़, थाना कोतवाली देहात में दबिश दी गई। कार्रवाई के दौरान दो अभियोग पंजीकृत करते हुए करीब 38 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। मौके से करीब 250 किलोग्राम लहन भी बरामद हुआ, जिसे टीम ने मौके पर ही नष्ट कर दिया। आबकारी टीम ने क्षेत्र में संचालित आबकारी दुकानों का भी निरीक्षण किया। दुकानों पर उपलब्ध स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया तथा बिक्री की स्थिति की जांच के लिए गुप्त रूप से टेस्ट परचेज भी कराया गया। इसके अलावा कबाड़ियों की दुकानों एवं ईंट-भट्ठों की गहनता से जांच की गई। अभियान के दौरान आबकारी विभाग की टीम ने ग्रामीणों को अवैध शराब के सेवन से होने वाले गंभीर नुकसान और जनहानि के प्रति जागरूक करते हुए अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री की सूचना विभाग को देने की अपील की।

सीए नरपत डुकिया बने राम मंदिर संचालन–प्रबंधन के प्रमुख, ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने की नियुक्ति

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

अयोध्या। अयोध्या में राम मंदिर में चंदा चोरी मामले के बाद मंदिर से जुड़े प्रबंधन को लेकर बड़े स्तर पर बदलाव का काम चल रहा है। मंदिर निर्माण में प्रोजेक्ट मैनेजर जगदीश आफले को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का पहला सचिव बनाए जाने के बाद अब CA नरपत डुकिया को मंदिर का संचालन और प्रबंधन का काम देखने का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं CEO पद के लिए आज इंटरव्यू लिया जाएगा।

ट्रस्ट ने 8 अगस्त 2026 को जारी अपने पत्र में बताया कि CA नरपत डुकिया को मंदिर संचालन एवं प्रबंधन इकाई का प्रमुख बनाया गया है। ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव डॉ। कृष्ण मोहन ने इस संबंध में आदेश जारी किया। साथ ही आचार्य इंद्रदेव मिश्र को नरपत डुकिया का सहयोगी नियुक्त किया गया है।

अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन के करीबी हैं डुकिया

नरपत डुकिया को अंतरिम महासचिव डॉक्टर कृष्ण मोहन का करीबी माना जाता है। डुकिया के पास मंदिर की समग्र प्रशासनिक व्यवस्था का समन्वय करने की जिम्मेदारी होगी। साथ ही डुकिया अलग-अलग विभागों के बीच तालमेल और व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे। उनके पास ट्रस्ट के फैसलों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी होगी।

इंद्रदेव मिश्र का कार्यकाल इस साल दिसंबर 2026 तक रहेगा। इंद्रदेव अयोध्या में राम वेद विद्यालय के प्रधानाचार्य भी हैं। उन्हें यह अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन लोगों पर मंदिर में होने वाले नित्य पूजन, यज्ञ, वैदिक अनुष्ठान और धार्मिक समिति के निर्देश के अनुसार अलग-अलग उत्सवों और कार्यक्रमों का संचालन करने की जिम्मेदारी होगी।

पिछले महीने आफले बने ट्रस्ट के पहले सचिव

चंदा चोरी का मामला सामने आने के बाद मंदिर में कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं। अब नई व्यवस्था के तहत प्रशासनिक प्रबंधन और धार्मिक अनुष्ठानों की जिम्मेदारियां अलग-अलग तय की जाएंगी। साथ ही धार्मिक व्यवस्थाओं के साथ प्रशासनिक कामकाज में बेहतर समन्वय पर जोर रहेगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से मंदिर प्रबंधन में बड़े स्तर पर बदलाव का सिलसिला जारी है। पिछले महीने जगदीश शंकर आफले को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का सचिव बनाया गया था। फिलहाल ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पद के लिए चयन की प्रक्रिया जारी है।

इंटरव्यू के लिए तैयारी, गोपनीयता पर फोकस

ट्रस्ट के CEO पद के लिए आए आवेदकों का आज इंटरव्यू लिया जाएगा। इस पद के लिए इंटरव्यू को लेकर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सारी तैयारी पूरी कर ली है। इस चयन प्रक्रिया में डेढ़ दर्जन से ज्यादा लोग शामिल किए गए हैं। इंटरव्यू को लेकर राम मंदिर परिसर में सुरक्षा और गोपनीयता पर विशेष जोर दिया गया है। पिछले दिनों सीईओ पद के लिए आवेदन मांगे गए थे, इसके लिए 5 हजार से अधिक लोगों ने आवेदन किया है। आफले को सचिव बनाए जाने के बाद अब सभी की नजर ट्रस्ट की कार्यकारिणी को मुख्य कार्यकारी (सीईओ) और प्रवक्ता की नियुक्ति पर लगी है। कहा जा रहा है कि प्रवक्ता की नियुक्ति प्रक्रिया भी फाइनल दौर में है और जल्द ही नाम का ऐलान हो सकता है।

टोल पर क्या हुआ था? टोल कर्मियों ने बताई– अतीक के बेटे के काफिले वाली गाड़ियों की कहानी

आर्यावर्त संवाददाता

प्रयागराज। माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद के काफिले में चल रही गाड़ियों के खिलाफ प्रयागराज के नवाबगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अब झांसी जेल में बंद अतीक के बेटे अली अहमद के काफिले के पीछे चल रहे समर्थकों के 10 वाहनों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। ये एफआईआर फतेहपुर के दो थानों में दर्ज कराई है।

कल्याणपुर और खागा में एफआईआर हुई है। दोनों कोतवाली में गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि इन दोनों टोल प्लाजा पर पैसा मांगने पर टोल कर्मियों से गाली-गलौज की गई। यही नहीं जान से मारने की नीयत से तेज रफ्तार में गाड़ी चढाने का प्रयास किया गया। वाहनों में बैठे लोगों पर बिना

पैसा दिए टोल बैरियर से गाड़ियां निकाल लीं।

भाई के जनाजे में शामिल होने गया था अली

बड़ौरी टोल प्लाजा के मैनेजर जितेंद्र सिंह की तहरीर पर कल्यानपुर थाने में केस दर्ज किया गया है। वहीं कटोघन टोल के सहायक मैनेजर सोनू सिंह की तहरीर पर खागा कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है। दो दिन पहले अली भाई अबान के जनाजे में शामिल होने के लिए गया था। वो पैरोल पर पुलिस अभिरक्षा में झांसी से प्रयागराज जाते समय फतेहपुर से गुजरा था। तभी ये सारी घटना हुई थी। केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है।

की जा रही है सीसीटीवी कैमरों फुटेज की जांच

काफिले में शामिल वाहनों के नंबरों और टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है। फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि वास्तव में घटना के दौरान हुआ क्या था? किन वाहनों में कौन लोग सवार थे? फिलहाल दोनों मामलों में मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपों की जांच कर रही है। जांच में जो भी तथ्य और सबूत सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद को लखनऊ जेल से प्रयागराज ले जाते समय नवाबगंज टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा हुआ। इसी दौरान उसके काफिले में शामिल करीब 25 से 30 निजी वाहनों ने बिना टोल दिए बैरियर पार कर लिया। टोल प्लाजा प्रबंधन की ओर से नवाबगंज थाने में मामले की तहरीर देकर एफआईआर दर्ज कराई गई।

गांव में तेंदुए का शावक दिखने से मचा हड़कंप

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। अखंडनगर थाना क्षेत्र के बछेड़िया गांव में मंगलवार को खेतों के पास तेंदुए का शावक दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। शावक नजर आने की खबर गांव में तेजी से फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण खेतों के आसपास पहुंच गए। सुरक्षा को लेकर ग्रामीण लाठी-डंडों के साथ पहरा दे रहे हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि यदि तेंदुए का शावक आसपास मिला है तो उसकी मां भी कहीं न कहीं आसपास मौजूद हो सकती है। इसी आशंका के चलते ग्रामीण खेतों की ओर जाने से बच रहे हैं और समूह में निगरानी कर रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस भी सतर्क हो गई। थानाध्यक्ष धीरेंद्र वर्मा ने बताया कि एसडीएम कादीपुर के निर्देश पर वन विभाग की टीम को मौके पर लगाया गया है। वन विभाग

की टीम आसपास तेंदुए की मौजूदगी के संकेत तलाशने के साथ ही पूरे मामले की जांच-पड़ताल कर रही है। पुलिस और वन विभाग की टीम स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। ग्रामीणों से सावधानी बरतने, अकेले खेतों की ओर नहीं जाने और किसी भी तरह की वन्यजीव गतिविधि दिखाई देने पर तत्काल पुलिस या वन विभाग को सूचना देने की अपील की गई है।

हर घर तिरंगा अभियान में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने संभाली कमान, यूपी में बन चुके 1.90 करोड़ राष्ट्रीय ध्वज

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा राष्ट्रीय ध्वज निर्माण का कार्य निर्धारित लक्ष्य और मानकों के अनुरूप समयबद्ध ढंग से पूरा कराया जाए तथा तैयार ध्वजों की आपूर्ति भी समय से सुनिश्चित की जाए। उनके निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मिशन निदेशक अरुण कुमार ने मंगलवार को लखनऊ के चिनहट विकासखंड की ग्राम पंचायत जुग्गौर और सिकंदरपुर का भ्रमण कर राष्ट्रीय ध्वज निर्माण कार्य का निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान मिशन निदेशक ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं से संवाद किया और उनके कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें विभिन्न आजीविका गतिविधियों एवं उद्यमों से जुड़कर आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने तुलसी मां स्वयं सहायता समूह, छोटे साहब स्वयं सहायता समूह और बजरंगबली स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से मुलाकात कर ध्वज निर्माण की प्रगति, गुणवत्ता और आपूर्ति व्यवस्था की जानकारी ली। इन समूहों को कुल 1.50 लाख राष्ट्रीय ध्वजों के निर्माण एवं वितरण का लक्ष्य दिया गया है, जिसके सापेक्ष अब तक लगभग 1.30 लाख राष्ट्रीय ध्वजों का निर्माण और वितरण किया जा चुका है। मिशन निदेशक ने महिलाओं के समर्पण, गुणवत्ता और समयबद्ध कार्य की सराहना करते हुए भरोसा जताया कि शेष लक्ष्य भी निर्धारित समय सीमा में पूरा कर लिया जाएगा।अरुण कुमार ने कहा कि 'हर घर तिरंगा' अभियान केवल राष्ट्रभक्ति की भावना से जुड़ा कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम भी बनकर उभरा है। स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं अपने परिश्रम, अनुशासन और सामूहिक प्रयास से राष्ट्रीय अभियान को सफल बनाने के साथ आत्मनिर्भरता की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय के नए अवसर पैदा हो रहे हैं तथा सामूहिक उद्यमिता को भी बढ़ावा मिल रहा है।मिशन निदेशक ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को 13 अगस्त तक दो करोड़ राष्ट्रीय ध्वजों के निर्माण का लक्ष्य मिला है। 10 अगस्त तक प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं द्वारा लगभग एक करोड़ 90 लाख राष्ट्रीय ध्वजों का निर्माण किया जा चुका है। उन्होंने इसे मिशन से जुड़ी महिलाओं की कार्यक्षमता, समर्पण और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण बताया।महिलाओं को संबोधित करते हुए अरुण कुमार ने कहा कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य महिलाओं को केवल किसी एक गतिविधि तक सीमित रखना नहीं, बल्कि उन्हें पूरे वर्ष स्थायी और विविध आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। इसके लिए विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को अलग-अलग आजीविका गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने महिलाओं से मसाला प्रसंस्करण इकाइयों, सौर ड्रायर आधारित उद्यमों, खाद्य प्रसंस्करण, सिलाई एवं परिधान निर्माण, अगरबत्ती निर्माण, डेयरी, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, हस्तशिल्प तथा स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित अन्य उद्यमों से जुड़ने का आह्वान किया।उन्होंने कहा कि मिशन महिलाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण, वित्तीय समावेशन, विपणन सहायता और बाजार से जोड़ने की दिशा में लगातार काम कर रहा है, ताकि उनकी आय में स्थायी वृद्धि हो सके। स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं अब केवल राष्ट्रीय ध्वज निर्माण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में सफल उद्यम स्थापित कर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम कर रही हैं।अरुण कुमार ने महिलाओं से सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाकर अपने उद्यमों का विस्तार करने और अन्य महिलाओं को भी आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं को संगठित शक्ति प्रदान कर रहे हैं और इनके माध्यम से महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होने के साथ अपने परिवार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।इस अवसर पर उपायुक्त (स्वतः रोजगार), लखनऊ ज्ञानेंद्र कुमार सिंह, राज्य मिशन प्रबंधक आचार्य शेखर तथा राज्य मिशन एवं जनपद स्तर के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

लखनऊ में ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से डिलीवरी बॉय की मौत, चालक फरार

लखनऊ। निगोहां थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात सड़क हादसे में एक डिलीवरी बॉय की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ, जब मोटरसाइकिल सवार युवक को पीछे से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली ने अपनी चपेट में ले लिया। दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया।पुलिस के अनुसार, 10 अगस्त 2026 की रात करीब 10:50 बजे नितिन चौरसिया (21) पुत्र सरवन निवासी मेरख नगर, थाना निगोहां, लखनऊ मोटरसाइकिल से कालिंदी नहर चौराहे की ओर से सेक्टर-12 चौराहे की तरफ जा रहे थे। जैसे ही वह सेक्टर-12 चौराहे से पूर्व नहर पुलिया चौराहे के पास पहुंचे, तभी पीछे से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आ गए। हादसे में नितिन गंभीर रूप से घायल हो गए।

सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायल को उपचार के लिए ट्रामा सेंटर भेजा गया।

बायोएनर्जी के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बना उत्तर प्रदेश : ए.के. शर्मा

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा, बायोएनर्जी, निवेश और नवाचार को नई गति देने वाले इंडिया बायोएनर्जी एंड टेक एक्सपो (आईबीईटी एक्सपो)-2026 का मंगलवार को ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में भव्य शुभारंभ हुआ। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने देश-विदेश से आए विशेषज्ञों, उद्योग प्रतिनिधियों, निवेशकों और प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश को बायोएनर्जी के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश आज कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में देश में आगे है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, संपीड़ित जैव गैस (सीबीजी) उत्पादन और रिकॉर्ड विद्युत आपूर्ति के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश अब शांतिपूर्ण और व्यापार के अनुकूल राज्य के रूप में भी अपनी पहचान बना रहा है।ए.के. शर्मा ने देश-विदेश के निवेशकों और उद्योग जगत से उत्तर प्रदेश में निवेश करने का आह्वान करते हुए कहा कि निवेशक प्रदेश में कहीं भी अपने संयंत्र स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की कानून-व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। सुरक्षित, शांतिपूर्ण और निवेश के अनुकूल वातावरण के कारण उत्तर प्रदेश देश और दुनिया के निवेशकों के लिए भरोसेमंद निवेश गंतव्य के रूप में उभरा है।उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बायोएनर्जी के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, गन्ना उत्पादन, कृषि अवशेष, जैविक अपशिष्ट और नगरीय ठोस कचरा बायोएनर्जी उत्पादन के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराते हैं। इन संसाधनों का वैज्ञानिक और तकनीकी उपयोग कर स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के साथ किसानों, युवाओं और उद्योगों के लिए रोजगार एवं आय के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश स्वच्छ, हरित और सतत ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार का प्रयास है कि नई ऊर्जा तकनीकों को प्रोत्साहन मिले, बड़े पैमाने पर निवेश आए, रोजगार के नए अवसर पैदा हों और पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को गति मिले।ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अब आवश्यकता इस बात की है कि कचरे को समस्या के रूप में देखने के बजाय उसे ऊर्जा, रोजगार और आर्थिक विकास के अवसर के रूप में देखा जाए।

साइबर अपराध के अंतरराज्यीय नेटवर्क पर पुलिस का बड़ा प्रहार

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। साइबर अपराध के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने एक महत्वपूर्ण प्रकरण में बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक 123 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहले चरण में 119 लोगों की गिरफ्तारी के बाद तकनीकी विश्लेषण, डिजिटल साक्ष्यों और आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने कोलकाता से तीन और गुजरात से एक अन्य महत्वपूर्ण आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई से साइबर अपराध से जुड़े अंतरराज्यीय नेटवर्क के कई अहम सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं।पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार 119 आरोपियों के कब्जे से बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फोन, कंप्यूटर और अन्य महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए थे। इन उपकरणों की तकनीकी जांच और डिजिटल डाटा के विश्लेषण के बाद जांच का दायरा बढ़ाया गया। इसके बाद पुलिस टीमों ने दूसरे राज्यों में कार्रवाई करते हुए कोलकाता से तीन और गुजरात से एक आरोपी को गिरफ्तार किया।पुलिस का कहना है कि जांच को केवल घटनास्थल तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि साइबर अपराध से जुड़े पूरे नेटवर्क, उसके संचालकों और सहयोगियों तक पहुंचने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। बरामद डिजिटल साक्ष्यों और तकनीकी तथ्यों का विस्तृत परीक्षण किया जा रहा है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अन्य संदिग्ध व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है और विवेचना आगे बढ़ने के साथ नई गिरफ्तारियां होने की संभावना से इंकार नहीं किया गया है।इस प्रकरण में पुलिस कार्रवाई की समग्र समीक्षा भी कराई गई। समीक्षा के दौरान सीसीटीवी फुटेज, अभिलेखों और अन्य साक्ष्यों की जांच की गई।

○ संक्षेप ○

डाक विभाग ने राखी भेजने के लिए 10 रुपये में उपलब्ध कराया वाटरप्रूफ लिफाफा

लखनऊ। भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व इस वर्ष 28 अगस्त को मनाया जाएगा। ऐसे में जो बहनें अपने भाइयों से दूर हैं या किसी कारणवश रक्षाबंधन के दिन उनसे मिल नहीं सकेंगी, उनके लिए डाक विभाग ने राखी भेजने की विशेष सुविधा उपलब्ध कराई है।लखनऊ जीपीओ की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि बहनों की राखी सुरक्षित रूप से उनके दूर रहने वाले भाइयों तक पहुंचाने के लिए वाटरप्रूफ राखी लिफाफे उपलब्ध कराए गए हैं। ये विशेष लिफाफे लखनऊ जनरल पोस्ट ऑफिस में मात्र 10 रुपये की कीमत पर मिल रहे हैं।डाक विभाग ने बताया कि बहनें इन वाटरप्रूफ राखी लिफाफों को खरीदकर उनमें अपनी राखी और भाई के प्रति प्रेम का संदेश रख सकती हैं तथा स्पीड पोस्ट के माध्यम से दूर रहने वाले भाइयों को भेज सकती हैं। इससे रक्षाबंधन के दिन दूरी के बावजूद भाई-बहन के रिश्ते की मिठास और अपनापन कायम रहेगा।लखनऊ जीपीओ ने बहनों से अपील की है कि वे समय रहते वाटरप्रूफ राखी लिफाफे प्राप्त कर अपनी राखी स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजें, ताकि रक्षाबंधन पर्व पर राखी सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंच सके।

निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए चार जिलों में बनेंगे आठ नए गो संरक्षण केंद्र

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में निराश्रित गोवंश के संरक्षण और उनके लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए चार जनपदों में आठ नए गो संरक्षण केंद्रों के निर्माण के लिए 12 करोड़ 80 लाख 96 हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। यह धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में खर्च की जाएगी।सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार स्वीकृत धनराशि से शाहजहांपुर, चित्रकूट, गाजीपुर और लखीमपुर में नए गो संरक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। शाहजहांपुर में पुवायां तहसील के ग्राम सिमरा वीरान में पांच केंद्रों का निर्माण प्रस्तावित है। इसके अलावा चित्रकूट के मानिकपुर तहसील स्थित ग्राम ददरी माफी, गाजीपुर के कासिमाबाद तहसील स्थित राजकीय बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र परजीपाह में एक केंद्र तथा लखीमपुर के मोहम्मदी तहसील स्थित ग्राम बरबर में एक गो संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा।सरकार ने प्रत्येक गो संरक्षण केंद्र के निर्माण के लिए 160.12 लाख रुपये की धनराशि का प्रावधान किया है। इन केंद्रों के निर्माण से निराश्रित गोवंश को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराने के साथ उनके संरक्षण और देखभाल की व्यवस्था को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।इस संबंध में पशुधन विभाग की ओर से शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश के माध्यम से निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। शासन ने स्पष्ट किया है कि स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार उपयोग सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी।निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग को केंद्रों के निर्माण में जारी धनराशि के नियमसंगत व्यय के साथ-साथ उपयोगिता प्रमाणपत्र, भौतिक प्रगति और निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है। सरकार ने निर्माण कार्यों की प्रगति और धनराशि के उपयोग पर प्रभावी निगरानी रखने के निर्देश भी दिए हैं।

हर घर तिरंगा अभियान में स्कूल-कॉलेजों में होंगी स्वतंत्रता आंदोलन आधारित प्रतियोगिताएं

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक आयोजित किए जा रहे 'हर घर तिरंगा अभियान-2026' के तहत दूसरे चरण में 9 से 12 अगस्त तक प्रदेश के सभी जिलों में स्कूल, कॉलेज और तकनीकी संस्थानों में स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाएगा। प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यालयों को आमंत्रित कर 26 जनवरी 2027 को सम्मानित किया जाएगा।पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि दूसरे चरण में तिरंगा महोत्सव के रूप में बड़े आयोजन किए जाएंगे। इसके अंतर्गत वृहद तिरंगा मेला और भव्य तिरंगा संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश स्तरीय तिरंगा महोत्सव किसी प्रमुख स्थल पर व्यापक जनभागीदारी के साथ आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक, सांसद, अन्य विशिष्ट व्यक्तियों और खिलाड़ियों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी।उन्होंने बताया कि तिरंगा मेले में ग्राम्य विकास विभाग के स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों के साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के सहयोग से निर्मित वस्तुओं को भी बिक्री एवं प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा।

ई-रिक्शा सवार महिला से चेन लूटने वाले तीन शातिर गिरफ्तार, दो चेन और वारदात में प्रयुक्त बाइक बरामद

लखनऊ। मड़ियांव पुलिस ने ई-रिक्शा से घर जा रही महिला के गले से सोने की चेन झपटकर फरार हुए तीन शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से पीली धातु की दो चेन और वारदात में प्रयुक्त स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों का पहले से भी आपराधिक इतिहास है। पूछताछ में आरोपियों से चेन और मोबाइल झपटमारी की कई घटनाओं का खुलासा हुआ है।पुलिस के अनुसार, 8 अगस्त 2026 को मोहित अवस्थी पुत्र ओम प्रकाश अवस्थी निवासी आम की बाग, बालाजी इन्क्लेव, निकट सिकरवार चौराहा, थाना मड़ियांव ने तहरीर देकर बताया था कि उनकी मां ई-रिक्शा से अपने घर जा रही थीं। घर के पास पहुंचने पर पीछे से आए एक अज्ञात युवक ने उनके गले से सोने की चेन झपट ली। इसके बाद वह कुछ दूरी पर मोटरसाइकिल लेकर खड़े अपने दो साथियों के साथ बैठकर फरार हो गया। तहरीर के आधार पर मड़ियांव थाने में मुकदमा संख्या 379/2026, धारा 304(2) बीएनएस के तहत तीन अज्ञात बाइक सवार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।घटना के खुलासे के लिए पुलिस टीम ने सुरागरसी-पतारसी, उपलब्ध साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू की।

जानकीपुरम में लाखों की चोरी का खुलासा, दो गिरफ्तार

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। जानकीपुरम थाना क्षेत्र में घर का ताला तोड़कर सोने-चांदी के आभूषण चोरी करने के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 26 लाख रुपये कीमत के चोरी के आभूषण व अन्य सामान, 3 लाख 97 हजार रुपये नकद, चोरी के पैसों से खरीदी गई क्लासिक बुलेट मोटरसाइकिल तथा घटना में प्रयुक्त होंडा न्यू वाहन बरामद किया है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों के खिलाफ लखनऊ और बाराबंकी के विभिन्न थानों में चोरी और गैंगस्टर एक्ट समेत कई मुकदमे पहले से दर्ज बताए गए हैं।पुलिस के अनुसार, 5 अगस्त 2026 को राम नरेश पुत्र स्वर्गीय जगत नारायण शुक्ला निवासी रामविहारी मार्ग, जानकीविहार, थाना जानकीपुरम ने पुलिस को सूचना दी थी कि उनके घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोर सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर ले गए हैं। सूचना के आधार पर जानकीपुरम थाने में मुकदमा संख्या 144/2026, धारा 305(ए) बीएनएस के तहत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। घटना की विवेचना उपनिरीक्षक विकास सिंह को सौंपी गई।घटना के खुलासे के लिए पुलिस उपायुक्त उत्तरी की सर्विलांस एवं क्राइम टीम तथा थाना जानकीपुरम की संयुक्त टीम को लगाया गया। पुलिस के मुताबिक 10 अगस्त 2026 को तड़के करीब 2:25 बजे मुखबिर की सूचना पर टीम ने मो. शोएब उर्फ सुहेल पुत्र मो. नसीम उर्फ मुल्ला निवासी ग्राम धधरा, थाना बड़ुपुर, बाराबंकी तथा रवि रावत उर्फ शाका पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम जमुआ, थाना घुंघटेर, बाराबंकी, हाल पता अभिषेकपुरम, थाना जानकीपुरम, लखनऊ को गिरफ्तार किया।

हज-2027 के चयनित यात्रियों को अग्रिम धनराशि जमा करने की समयसीमा बढ़ी

लखनऊ। हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई ने हज-2027 के लिए प्रोविजनली चयनित हज यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए अग्रिम धनराशि जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। पहले 10 अगस्त 2026 तक जमा की जाने वाली 1,52,300 रुपये की अग्रिम धनराशि अब 17 अगस्त 2026 तक जमा की जा सकेगी।हज कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से जारी सर्कुलर-6 के माध्यम से यह जानकारी दी गई है। इसके अनुसार प्रत्येक प्रोविजनली चयनित हज यात्री को निर्धारित अग्रिम धनराशि हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई के खाते में तय समय सीमा के भीतर जमा करनी होगी। समय पर धनराशि जमा नहीं करने पर संबंधित यात्री की हज यात्रा के लिए प्रोविजनल सीट निरस्त कर दी जाएगी।चयनित हज यात्री अग्रिम धनराशि ऑनलाइन माध्यम से भी जमा कर सकते हैं।

चोरी के आरोपी को पुलिस अभिरक्षा से फरार होने के बाद फिर दबोचा, एक मोबाइल बरामद

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। ठाकुरगंज पुलिस ने घर में चोरी की घटना में शामिल आरोपी को पुलिस अभिरक्षा से फरार होने के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से चोरी किया गया ओप्पो कंपनी का गहरे नीले रंग का मोबाइल फोन बरामद हुआ है। आरोपी के खिलाफ चोरी समेत कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं।पुलिस के मुताबिक, 8 अगस्त 2026 को सुशीला साहू पत्नी शत्रोहन साहू निवासी पन्नी वाली गली, निवाजगंज चौराहा, थाना ठाकुरगंज ने तहरीर देकर बताया था कि 7 अगस्त की रात करीब 2:30 बजे अज्ञात व्यक्ति छत के रास्ते उनके घर में घुस आया और अलमारी में रखी नगदी व ओप्पो कंपनी का मोबाइल चोरी कर फरार हो गया। तहरीर के आधार पर ठाकुरगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की।सीसीटीवी फुटेज, अन्य साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने 9 अगस्त की रात करीब 11:40 बजे घटना में शामिल शानू उर्फ मो. समद पुत्र स्वर्गीय रईस उर्फ शाहिल निवासी रईस नगर, जामा मस्जिद के पीछे, तहसीनगंज, थाना ठाकुरगंज को गुलालाघाट क्षेत्र से गिरफ्तार किया था।पुलिस के अनुसार, थाने में निरुद्ध रहने के दौरान आरोपी ने सुबह शौच जाने का अनुरोध किया। संतरी ड्यूटी पर तैनात आरक्षी की निगरानी में उसे थाना परिसर स्थित शौचालय भेजा गया। इसी दौरान आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। घटना के संबंध में ठाकुरगंज थाने में अलग से मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए चार पुलिस टीमों का गठन किया गया।लगातार तलाश के बाद ठाकुरगंज पुलिस टीम ने 11 अगस्त 2026 को शानू उर्फ मो. समद को सआदतगंज थाना क्षेत्र में चौपटिया रोड स्थित लल्ला बिरयानी शॉप के पास से गिरफ्तार कर लिया।

दो युवकों की मौत से हड़कंप, होटल के कमरे में फंदे से लटका मिला युवक

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। राजधानी में सोमवार देर रात से मंगलवार सुबह तक अलग-अलग थाना क्षेत्रों में फांसी लगाने की दो घटनाओं से हड़कंप मच गया। गोमतीनगर के विवेकखंड-4 स्थित एक होटल के बंद कमरे में युवक का शव पंखे से रस्सी के सहारे लटका मिला। वहीं, ठाकुरगंज क्षेत्र में एक 30 वर्षीय युवक ने घर की छत पर बने कमरे में फांसी लगा ली। दोनों मामलों में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फॉरेंसिक टीम की मदद से घटनास्थल की जांच कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। दोनों घटनाओं में फांसी लगाने के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल सका है। गोमतीनगर थाना क्षेत्र के विवेकखंड-4 स्थित होटल दि एलीट इन के मैनेजर ने 10 अगस्त 2026 की रात करीब 8:30 बजे पुलिस को सूचना दी कि होटल का कमरा नंबर 301 दोपहर से बंद है। काफी देर तक कमरा नहीं खुलने पर होटल कर्मचारियों को संदेह हुआ, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक उपनिरीक्षक शिवम गुप्ता और पुलिस बल के साथ होटल पहुंचे। पुलिस ने जांच की तो कमरा अंदर से बंद मिला। दरवाजे की दरार से देखने पर कमरे के भीतर एक व्यक्ति पंखे से रस्सी के सहारे लटका दिखाई दिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया।फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए। इसके बाद होटल कर्मचारियों की सहायता से युवक को फंदे से नीचे उतारा गया और चिकित्सकीय परीक्षण के लिए ट्रॉमा सेंटर, केजीएमयू भेजा गया। वहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया।पुलिस होटल के अभिलेखों और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर युवक की पहचान और उसके होटल में ठहरने से जुड़ी जानकारी जुटा रही है। कमरे के अंदर से बंद होने के कारण भी पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। प्रारंभिक स्तर पर फांसी लगाने के कारणों की पुष्टि नहीं हो सकी है।दूसरी घटना ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के सुन्दर नगर, फरीदीपुर में सामने आई। यहां 30 वर्षीय आरजू सिंह पुत्र प्रमोद कुमार सिंह ने घर की छत पर बने कमरे में फांसी लगा ली। पुलिस को सूचना मृतक के भाई अभय सिंह ने दी।अभय सिंह के अनुसार, मंगलवार सुबह करीब 7:30 बजे वह अपने भाई को जगाने के लिए छत पर बने कमरे में गए थे। कमरे में पहुंचने पर उन्होंने आरजू सिंह को बल्ली से रस्सी का फंदा बनाकर लटका देखा।

नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में युवक गिरफ्तार

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। थाना मोहनलालगंज क्षेत्र में 16 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने किशोरी को भी सकुशल बरामद कर लिया। आरोपी के विरुद्ध संबंधित धाराओं में विधिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।पुलिस के अनुसार, मोहनलालगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने सूचना दी थी कि 26 जुलाई 2026 की रात उसकी 16 वर्षीय पुत्री आभूषण और नगदी लेकर घर से चली गई है। जानकारी करने पर पता चला कि गांव फत्तेखेड़ा मजरा कनकहा निवासी सनी पुत्र स्वर्गीय अशोक कुमार भी अपने घर पर मौजूद नहीं था। इस संबंध में जानकारी करने पर विपक्षी पक्ष की ओर से महिला के साथ विवाद किया गया तथा उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई।महिला की तहरीर के आधार पर थाना मोहनलालगंज में मुकदमा संख्या 278/2026, धारा 87, 137(2) और 351(3) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए, पीड़िता की सकुशल बरामदगी और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के निर्देश पर दो पुलिस टीमों का गठन किया गया।पुलिस टीमों ने तकनीकी एवं मैनुअल साक्ष्यों के साथ स्थानीय सूचना तंत्र की मदद से लगातार तलाश शुरू की। इसी क्रम में 11 अगस्त को पुलिस ने आरोपी सनी को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से किशोरी को भी सकुशल बरामद किया गया।

भारत में कॉकरोचों का ज्वालामुखी फूट पड़ा

नरेंद्र मोदी को समय विशेष ने भारत का प्रधानमंत्री बनाया था। अब समय ही जुलाई 2026 में बता रहा है कि उनकी एक्सपायरी के साथ संघ परिवार और हिंदू राजनीति का भी तिया-पांचा नत्थी है! कैसे? बुनियादी बात यह है कि मोदी राज ने हिंदुओं के चाल, चेहरे और चरित्र का वह खुलासा देश (अर्थात भारत की मिलेनियल, जेन-ज़ेड और अल्फा पीढ़ी) तथा दुनिया (अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन से लेकर आसियान और पड़ोसी देशों तक) के सामने ला दिया है। इसका लब्बोलुआब है कि उसकी 'चाल' देश को पराश्रित और बिकाऊ बाजार बनाने की है, उसका 'चेहरा' मनुष्य को कॉकरोच मानने वाला है और उसका 'चरित्र' नैतिकताविहीन भय, भूख और भक्ति पर टिका है। तभी हिंदुओं की मौजूदा युवा पीढ़ी और अगली पीढ़ी के बीच कथित चाल, चेहरा और चरित्र मजाक, मखौल और घृणा का विषय है।

जरा मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर से जुलाई 2026 तक की घटनाओं पर गौर करें। क्या एक भी ऐसी घटना हुई, जिससे प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की जैविक वाहवाही हुई? सरकार ने शक्ति और जीत का जैसा जो नैरेटिव बनाया, उस पर देश-दुनिया की प्रतिक्रिया क्या थी? मोदी-शाह भले इस गलतफहमी में रहे हों कि भक्त झूम रहे हैं। 2024 के आम चुनाव में अप्रत्याशित झटके के बाद उन्होंने हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, असम जीत लिए। भक्तों ने नगाड़ा भी बजाया। पर जितना बजाया, उससे अधिक साख बिगड़ी। हिंदू राजनीति का चाल, चेहरा और चरित्र लुढ़का। सोचें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद विश्व राजनीति में भारत का जलवा बना या पाकिस्तान का? वैसे ही भारत में मोदी, भाजपा और संघ की हर जीत, चुनाव आयोग, संसदीय कार्यवाही, सुप्रीम कोर्ट आदि हर संस्था की साख का भ_ा बैठाने वाली थी। क्या है चुनाव आयोग की अब साख? भारत के चीफ जस्टिस ने 15 मई 2026 को एक ही तो शब्द बोला था। पर भारत में कॉकरोचों का ज्वालामुखी फूट पड़ा।

यह ज्वालामुखी न शांत होना है और न खत्म। पहली बात, 35 वर्ष से नीचे की उम्र के नौजवानों की संख्या कुल आबादी में आज कोई 65 प्रतिशत है। इसमें भी 15 से 29 वर्ष की पीढ़ी (जनरेशन-ज़ेड) कोई 37 करोड़ है। इसी में फिर आगे जुड़ने वाले 15 साल से कम उम्र के बच्चों की करोड़ों की वह संख्या है जो 2029 और 2034 के आम चुनावों में वोट देगी। ये स्कूली बच्चे भी कॉकरोच आंदोलन की हवा के मीम्स की अफीम का मजा लेते हुए है। क्या इन्हें नरेंद्र मोदी अपनी रील्स बनाकर नौकरियों की हवा बनाएगे? अच्छे दिन, पैसा बांटने, नौकरियों के प्रमाणपत्रों की झांकियों, राष्ट्रवाद और भक्तिवाद से नई और भावी पीढ़ी में जितने भ्रम बनाए थे, उनकी पूर्ति मोदी रील्स से कतई पूरी नहीं होगी?

सो, मोदी-शाह और संघ ने जो कांटे बोए, जितनी तरह के झूठ बोले, उन्हीं से घर-घर ठगी का रोना है। मोदी का चेहरा अकेला सरकार, संघ परिवार की पूंजी था। मोदी ने स्वयं घर-घर मोदी, हर-हर मोदी बनाया था। वही चेहरा चेहरा अब नौजवानों का मीम है, गुस्से और गालियों का केंद्र है। मजाक, मखौल और गालियों की खान बना हैं। दूसरा कोई भी चेहरा भाजपा और संघ और स्वंय मोदी के पास नहीं है, जिसे आगे कर जिसकी सच्चाई, जिसके प्रति विश्वास से युवाओं के गले बात उतारी जा सके। न ही सरकार की किसी संस्था की धमक है और न मान। कॉकरोच भीड़ की निगाह में मोदी सरकार की हर संस्था, लोकतंत्र का खंभा अब भरोसा लायक नहीं है।

सोचें, कॉकरोच, सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके पर। कल तक अनाम और जीरो। अचानक नौजवानों के दिल-दिमाग पर छाए, इनके बहाने ज्वालामुखी फूटा। पर बेचारे वांगचुक ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के हाथ से जूस पीया नहीं कि नौजवानों ने उनसे नाता तोड़ डाला। भाजपाई चेहरे जैसे अछूत हों! फिर संसद बैठी, तो लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के दौरान स्पीकर पद पर बैठे ओम बिरला का चेहरा देखा तो कॉकरोच के साथ घर-घर सोचा यह कैसा स्पीकर है।

सो, मां भारती के नाम पर संघ परिवार और भाजपाई हिंदू संस्कृति का हवाला देते हुए बुजुर्गों के सम्मान, प्रधानमंत्री की गरिमा के नाम पर नरेंद्र मोदी के मखौल को कितना ही असंस्कारी घोषित करें, लेकिन यह नया असंस्कारी भारत मोदी, संघ परिवार की ही बदौलत है। मां भारती के नाम पर झूठ बोलकर धोखा देने, राजनीति को अनैतिकताओं का कोठा बनाने, नेताओं को खरीदने-बेचने, डराने-धमकाने, किसी को पप्पू बताने, किसी को देशद्रोही, खालिस्तानी या टुकड़े-टुकड़े गैंग घोषित कर देने की नंगई ने ही युवाओं, बच्चों को जैसे को तैसी भाषा दी है। कल तक सोशल मीडिया, टीवी चैनल मोदी की ताकत है। वही सोशल मीडिया अब उनका पानीपत मैदान है। हिंदुओं की त्रासदी और मोदी व हिंदू राजनीति की एक्सपायरी है।

कभी-कभी एक शब्द भी गजब ढाता है

फिर उस ने कुछ ही दिनों में उन्हें अपदस्थ कर डाला। उस सरकार को हिला दिया जिसे बारह साल से कोई दल या नेता झुकाने में विफल रहा था।

शंकर शरण

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने दिया था। उन के शब्दों ने हिटलर के सामने पस्त हो रहे इंग्लैंड को बल दिया। इस हद तक कि कई यूरोपीय देशों को टिके रह कर लड़ने का हौसला मिला।ज. चर्चिल ने अंग्रेजी भाषा को बुलाया और उसे युद्धभूमि में उतार दिया। आज कम लोग याद करते हैं कि चर्चिल को 1953 में साहित्य का नोबल पुरस्कार मिला था — इतिहास और साहित्यिक लेखन, तथा उदात्त मानवीय मूल्यों की रक्षा में अद्भुत वक्तृता के लिए।ज कला के किसी अन्य माध्यम में इतने शक्ति-संचय और प्रभाव की संभावना नहीं है। देखें तो एक शब्द — 'कॉकरोच — ने निवर्तमान शिक्षा मंत्री के पद की बलि ले ली। चाहे इस से उन का संबंध नहीं था। पर सामाजिक क्षेत्र में प्रयोग होकर वह शब्द तीखा बन गया था। उस का जन्म हिकारत और घमंड की भावना से हुआ था। इसलिए 'पार्टी रूप में शरीर पाकर एक कोरे शब्द ने शक्ति रूप धारण कर लिया। वह बलि माँगने लगा, और परिस्थितिवश उस के सामने शिक्षा मंत्री पड़ गये!

फिर उस ने कुछ ही दिनों में उन्हें अपदस्थ कर डाला। उस सरकार को हिला दिया जिसे बारह साल से कोई दल या नेता झुकाने में विफल रहा था। पर चार दिन पहले बनी कॉकरोच जनता पार्टी, जो कहीं औपचारिक दर्ज भी नहीं, ने सीधी झड़प में उसे झुकाया। यदि 'कॉकरोच शब्द उस सामाजिक अर्थ में उच्चरित होकर अवतरित न हुआ होता, तो क्या भारतीय राजनीति में वह होता जो गत सप्ताह हुआ?

कॉकरोच पार्टी बनाने से पहले अभिजीत दीपके एक साधारण छात्र था। वह वही बना रहता, यदि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 15 मई 2026 को इस शब्द का वैसा प्रयोग न किया होता। जिस का समाचार हजारों मील दूर दीपके ने सुनकर अपना क्षोभ व्यक्त करने के लिए उस नाम से एक व्यंग्यात्मक पार्टी बनाई। महज शाब्दिक! जैसे कॉकरोच नाम भर था, वैसे ही कॉकरोच पार्टी भी। एक एक्स (ट्विटर) मंच, जहाँ उस ने वैसे 'कॉकरोचों को इक_ा होने की अपील की। ऐसी गतिविधि सोशल मीडिया पर हजारों लोग करते रहते हैं। दुनिया भर में बड़े-बड़े सितारे, नेता, लेखक, पत्रकार ट्विटर पर कुछ न कुछ लिखते बोलते हैं और उन के लाखों फॉलोअर उसे लाइक करते हैं। उस से कुछ नहीं होता।

पर इस सामाजिक शब्द, 'कॉकरोच, का जिस रूप में जन्म हुआ उस में तीखा अर्थ भरा हुआ था। चीफ जस्टिस ने 15 मई को अपनी अदालत में किंचित वितृष्णा से कहा, कुछ युवक कॉकरोच की तरह होते हैं, जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता और किसी भी पेशे में उनके लिए कोई स्थान नहीं होता। उनमें से कुछ मीडिया में चले जाते हैं, कुछ आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं, और फिर वे हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। उन की बात में सत्य का अंश था। कुछ लोग किसी बड़े व्यक्ति या संस्था को निशाना बनाकर सफल होने की तिकड़म करते ही रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर करना इस का एक साधन रहा है।

परन्तु जिस तरह चीफ जस्टिस ने हल्के से वैसे लोगों को 'बेरोजगार युवक कह दिया, वह बात एक तिक्त युवा समूह पर जाकर बैठ गई। यानी, उन भरे बैठे बेरोजगार युवकों पर जो कई तरह से योग्य होते हुए भी शासकों के भ्रष्टाचार, जातिवाद, आरक्षण, दलबंदी, स्थान की कमी, कुशिक्षा, आदि कारणों से बेकारी, और फलतः उपेक्षा व कष्ट झेलते हैं।

सो चीफ जस्टिस के उस शब्द की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया हुई। दूसरे दिन,16 मई को, दीपके ने उस शब्द से 'कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक ट्विटर हैंडल बनाया। एक ही दिन में उस के उनतीस हजार फॉलोअर बन गये। चार दिन में उन की संख्या दो लाख हो गई। पाँचवें दिन सत्ताधारियों के दबाव से ट्विटर ने भारत में उस हैंडल को हटा दिया। छठे दिन, 22 मई को दीपके ने 'कॉकरोच इज बैक नाम से नया हैंडल बनाकर 'कॉकरोचों द्वारा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा माँगने का अभियान आरंभ किया, क्योंकि कई परीक्षाओं के पर्चे लीक होने से देश भर के छात्रों को बार-बार परेशानी हो रही थी। इस अनायास आह्वान ने देश के युवाओं के क्षोभ को एक रास्ता और स्वर दे दिया। जो सत्ताधारियों की लापरवाही और गैर-जबावदेही से दुःखी थे। उस दुःख को 'कॉकरोच बिल्ले के क्षोभ ने एक नैतिक धार दे दी। एक तो, उन्हें देश के सत्ताधारी वितृष्णा से देखते हैं — आखिर न्यायाधीश सरकार का तीसरा अंग हैं। दूसरे, पर्चे लीक एवं शैक्षिक तंत्र की लापरवाहियों के लिए कोई जिम्मेदार नहीं! प्रधानमंत्री आए-दिन कुछ कुछ बोलते रहते हैं, पर लाखों छात्रों के साथ हो रहे अन्याय पर चुप बने रहे हैं।

फलतः यह दोहरा आक्रोश जुड़ कर दीपके द्वारा 22 मई को एक ठोस माँग में परिणत हुआ। फिर उस ने 6 जून को जंतर-मंतर पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए धरना शुरू किया। उस में जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी आ जुड़े। फिर उन के समर्थन में बड़े लोग बयान देने लगे। इस प्रकार, शिक्षा तंत्र में लापरवाही की जिम्मेदारी के लिए मंत्री के इस्तीफे की माँग एक भौतिक शक्ति बन गई। उस ने अन्य शक्तियों को भी आकर्षित किया। इस तरह, 15 मई को 'कॉकरोच शब्द के जन्म लेने, अगले दिन उस की प्रतिक्रिया में ट्विटर पर 'कॉकरोच पार्टी बनने, वहीं 22 मई को 'कॉकरोच द्वारा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की माँग का आरंभ, फिर 6 जून से जंतर-मंतर धरना, और अंततः 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री का इस्तीफा — यह सब मूलतः उस एक शब्द के उच्चारण से बनी गति है। चीफ जस्टिस का कहा एक शब्द अनजाने पूरी सरकार पर भारी पड़ गया। यदि वह शब्द उस रूप में उच्चरित और अवतरित न हुआ होता, तो गत दो महीने की घटनाएं शायद ही घटी होती। यह संयोग भी था। परन्तु एक शब्द की शक्ति भी, जो कभी-कभी कैसा रूप दिखा सकती है! इस से पहले भारतीय राजनीति में एक शब्द का प्रभाव छब्बीस वर्ष पहले देखा गया था। जब भाजपा के उभरते नेता गोविंदाचार्य ने 1997 में अपने सर्वोच्च नेता वाजपेई के लिए 'मुखौटा शब्द का प्रयोग किया था। यद्यपि उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। पर स्वयं भाजपा के बड़ों द्वारा उसे सत्य मानने से बात जमी रह गई। तब के हालात में वह शब्द सही लगता भी था। पर जल्द ही गोविंदाचार्य को भुगतना पड़ा। उन का राजनीतिक कैरियर ही खत्म हो गया। पहले उन्हें किनारे किया गया। फिर पार्टी में उन की कोई जगह न बन सकी। वरना, वे एक स्टार नेता थे। उन का व्यक्तित्व, वक्तृता, जाति, पार्टी, आयु, सब कुछ संभावनाओं से भरा था। पर उस एक शब्द प्रयोग ने उन को ग्रहण लगा दिया। सो, कभी-कभी एक शब्द भी गजब ढाता है! यह भाषा की रहस्यमय शक्ति है। यद्यपि वह अपने आप में दुर्बल है। जो चाहे इस का दुरुपयोग कर लेता है! इसीलिए कवि अज्ञेय ने भाषा को 'सभी कला माध्यमों में सबसे कमजोर बताया था। जिसे आसानी से तोड़ा-मरोड़ा, भ्रष्ट किया जा सकता है! किसी साधारण या घटिया वस्तु, पर्चा, भाषण, नेता, आदि – को भी 'सर्वोत्तम, 'शानदार, 'महान, 'ऋषि, आदि कह कर धड़ल्ले से परोसा जाता है। सत्ता, धन, संगठन, प्रचार, आदि बल से लफ्फाजी रूप में भाषा का दुरुपयोग होता है। तब वह लोगों को दुष्प्रभावित कर सकती है। वैसी स्थिति में, ठगे जाते लोगों का तो क्या, भाषा अपना भी बचाव नहीं कर पाती! इस रूप में, संगीत, चित्र, आदि कला-माध्यमों की तुलना में भाषा कमजोर है। इस का सर्वाधिक दुरुपयोग होता है। दूसरे कला माध्यमों का इतना दुरुपयोग नहीं हो सकता। फिर भी, यही भाषा कभी-कभी अपने प्रयोग करने वाले को भारी चकमा भी देती है। इसलिए साहित्य ही नहीं, राजनीति में भी भाषा के प्रयोग के प्रति सावधानी रखना आवश्यक है।

व्यंग्य

रोड-रोलर रुख

संसदीय परंपरा के तहत निचले सदन में विपक्ष के नेता को 'प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग' कहा जाता है। इस रूप में कई राजनीति-शास्त्री इसे प्रधानमंत्री के बाद सबसे महत्त्वपूर्ण पद बताते हैं। इस मान्यता के पीछे प्रमुख तर्क है कि नेता विपक्ष सरकार से असहमत पूरे जनमत की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकतांत्रिक अपेक्षा यह है कि इन भावनाओं की भी कद्र की जाए। तो कहा जाता है कि पक्ष- विपक्ष दोनों लोकतांत्रिक शासन-व्यवस्था के अंग हैं। लेकिन यह स्थिति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेता विपक्ष सवाल पूछते हुए पत्र लिखें, और गृह मंत्री उसकी पावती भेजने की जरूरत भी ना समझें। लो

कसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 25 जुलाई को भेजे पत्र में अमित शाह से पूछा था कि 20 जुलाई को छात्र- नौजवानों के 'संसद मार्च' के दौरान घातक हथियारों के इस्तेमाल तथा सादी पोशाक में 'सुरक्षाकर्मियों' की तैनाती का आदेश किसने दिया? 29 जुलाई को गांधी ने बताया कि जवाब तो दूर, पत्र का एक्नॉलेजटमेंट तक उन्हें नहीं मिला है। गांधी ने वही प्रश्न लोकसभा में पूछे, लेकिन वे शोरगुल और हंगामे के बीच कहीं दब गए। गांधी का कहना है कि चूंकि दिल्ली पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ (जिन एजेंसियों की तैनाती थी) केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करते हैं, अतः दिल्ली में जो हुआ- अगर वह शाह की जानकारी में हुआ तो सारी जवाबदेही उनकी बनती है।

अगर प्रदर्शनकारियों पर 'क्रूर हमले' की जानकारी उन्हें नहीं थी, तो शाह अयोग्य गृह मंत्री माने जाएंगे। इन दोनों ही स्थितियों में अमित शाह का गृह मंत्री बने रहना अस्वीकार्य हो गया है। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि अमित शाह की जवाबदेही का सवाल फिलहाल कांग्रेस का मुख्य मुद्दा है। इस तरह संसद और उसके बाहर टकराव एक नया फ्लैश प्वाइंट तैयार हो गया है। ऐसा संभवतः नहीं होता, अगर शाह विपक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते और दिल्ली की घटनाओं की निष्पक्ष जांच का एलान कर देते। मगर ऐसी बातों की अपेक्षा अब सदिच्छा भर मालूम पड़ती है। इसलिए सरकार के रोड-रोलर रुख ने संवाद से समाधान निकालने के सिस्टम को ही गतिरुद्ध कर रखा है।

ब्लॉग

ढाका की राजनीति और भारत-बांग्लादेश संबंधों की नई परीक्षा

ललित गर्ग

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा दिसंबर 2026 में स्वदेश लौटने की घोषणा केवल एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि यह दक्षिण एशिया की बदलती भू-राजनीति, लोकतांत्रिक मूल्यों और भारत-बांग्लादेश संबंधों की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम बन गया है। जिस समय बांग्लादेश की राजनीति सत्ता परिवर्तन, वैचारिक ध्रुवीकरण और संस्थागत अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, उसी समय शेख हसीना ने यह घोषणा कर राजनीतिक विमर्श को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। उनका यह कहना कि 'गिरफ्तारी, जेल या मृत्यु का भय भी उन्हें अपने देश लौटने से नहीं रोक सकता', उनके समर्थकों के लिए भावनात्मक आह्वान है तो विरोधियों के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती। बांग्लादेश में पिछले वर्ष सत्ता परिवर्तन के बाद जो राजनीतिक वातावरण बना, उसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता और राजनीतिक सहिष्णुता पर लगातार प्रश्न उठते रहे हैं। बांग्लादेश में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा शेख हसीना के विरुद्ध सुनाया गया फैसला और उसके बाद उनके समर्थकों पर बढ़ती कार्रवाइयों ने यह संकेत दिया कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा धीरे-धीरे प्रतिशोध की राजनीति में बदलती जा रही है। हाल ही में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल रहे पूर्व क्रिकेट कप्तान साकिब अल हसन के घर पर हुआ हमला भी इस बात का संकेत है कि राजनीतिक असहमति अब सामाजिक तनाव का रूप लेने लगी है। दूसरी ओर, प्रधानमंत्री तारिक रहमान के एक करीबी सहयोगी द्वारा शेख हसीना को 'तुरंत लौटकर सामना करने' की चुनौती देना बताता है कि बांग्लादेश का राजनीतिक वातावरण अभी भी सामान्य नहीं हुआ है। राजनीति

लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक दल या नेता से असहमति स्वाभाविक है, किंतु असहमति का समाधान न्यायपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया और स्वतंत्र संस्थाओं के माध्यम से होना चाहिए। यदि किसी नेता की लोकप्रियता का उत्तर प्रतिबंध, दमन या भय के वातावरण से दिया जाए, तो लोकतंत्र की आत्मा कमजोर होती है। शेख हसीना की वापसी को केवल एक व्यक्ति की वापसी के रूप में नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा की परीक्षा के रूप में देखा जाना चाहिए। यदि अवामी लीग को राजनीतिक प्रक्रिया से बाहर रखने की कोशिश होती है, तो यह बांग्लादेश के लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाएगा। वास्तविकता यह भी है कि बांग्लादेश की राजनीति आज केवल अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनललिस्ट पार्टी (बीएनपी) के बीच सत्ता संघर्ष तक सीमित नहीं रह गई है। अब यह संघर्ष राष्ट्र की ऐतिहासिक पहचान, 1971 के मुक्ति संग्राम की विरासत और भविष्य की वैचारिक दिशा का भी बन चुका है। अवामी लीग स्वयं को मुक्ति संग्राम की मूल चेतना का प्रतिनिधि बताती है, जबकि बीएनपी भी अब उसी विरासत पर अपना दावा प्रस्तुत कर रही है। इतिहास की इस प्रतिस्पर्धी व्याख्या ने राजनीतिक ध्रुवीकरण को और गहरा किया है। ऐसी परिस्थितियों में शेख हसीना की वापसी केवल राजनीतिक समीकरण नहीं बदलेगी, बल्कि राष्ट्रीय विमर्श की दिशा भी प्रभावित करेगी।

इन परिस्थितियों में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत और बांग्लादेश के संबंध केवल दो पड़ोसी देशों के रिश्ते नहीं हैं, बल्कि साझा इतिहास, संस्कृति, भाषा, आर्थिक सहयोग और सामरिक हितों पर आधारित हैं। पिछले डेढ़ दशक में दोनों देशों के संबंधों में अभूतपूर्व निकटता आई, जिसका एक बड़ा आधार शेख हसीना सरकार और नई दिल्ली के बीच बना विश्वास था। सीमा विवादों का समाधान, ऊर्जा सहयोग, संपर्क परियोजनाएं, आतंकवाद के विरुद्ध साझा कार्रवाई तथा पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी जैसे अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई। लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिवर्तन ने इस विश्वास की नई परीक्षा शुरू कर दी है। नई दिल्ली ने एक ओर शेख हसीना को सुरक्षा और आश्रय दिया है, वहीं दूसरी ओर उसने ढाका की नई सरकार से संवाद भी जारी रखा है। यही परिपक्व कूटनीति का परिचायक है। भारत के सामने चुनौती किसी एक राजनीतिक दल के साथ खड़ा दिखाई देने की नहीं, बल्कि पूरे बांग्लादेश के साथ स्थायी और संतुलित संबंध बनाए रखने की है। इसी संदर्भ में नई दिल्ली में आयोजित होने वाला बारहवाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर बन सकता है। यदि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान इसमें भाग लेते हैं और भारत के शीर्ष नेतृत्व के साथ सकारात्मक संवाद होता है, तो दोनों देशों के बीच हाल के तनावों को कम करने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। यह केवल औपचारिक शिखर बैठक नहीं होगी, बल्कि दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली का अवसर भी होगी। भारत को इस मंच का उपयोग केवल आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता, लोकतांत्रिक मूल्यों और सुरक्षा सहयोग पर भी स्पष्ट संवाद स्थापित करना चाहिए। सरकार

भारत के सामने अनेक जटिल प्रश्न भी हैं। गंगा जल संधि के नवीनीकरण, तीस्ता जल बंटवारे, सीमा-पार व्यापार, अवैध घुसपैठ, सीमा सुरक्षा तथा शेख हसीना के प्रत्यर्पण जैसे मुद्दे आने वाले समय में द्विपक्षीय संबंधों की दिशा तय करेंगे। इनमें किसी भी विषय पर भावनात्मक या राजनीतिक प्रतिक्रिया के बजाय कानूनी, कूटनीतिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक होगा। विशेष रूप से प्रत्यर्पण का प्रश्न केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कानून और राजनीतिक परिस्थितियों से भी जुड़ा हुआ है। भारत को अपनी संधियों, न्यायिक प्रक्रियाओं और रणनीतिक हितों के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ना होगा। दूसरी ओर बांग्लादेश में चीन का बढ़ता प्रभाव भी नई दिल्ली के लिए चिंता का विषय है। वर्तमान सरकार के शुरुआती महीनों में चीन के साथ बढ़ते संपर्क और सामरिक महत्व की परियोजनाओं पर समझौते इस बात का संकेत हैं कि ढाका अपनी विदेश नीति में संतुलन साधने का प्रयास कर रहा है। भारत के लिए आवश्यक है कि वह प्रतिस्पर्धा की मानसिकता के बजाय विश्वास और विकास की साझेदारी को प्राथमिकता दे। यदि भारत आर्थिक सहयोग, निवेश, आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी साझेदारी के नए अवसर विकसित करता है, तो दोनों देशों के संबंध और अधिक मजबूत हो सकते हैं।

शेख हसीना की वापसी का प्रश्न अंततः बांग्लादेश के लोकतांत्रिक चरित्र की परीक्षा है। यदि उन्हें निष्पक्ष राजनीतिक अवसर मिलता है, तो जनता स्वयं तय करेगी कि भविष्य का नेतृत्व किसे सौंपना है। लेकिन यदि राजनीतिक प्रतिशोध, दमन और हिंसा का वातावरण बना रहता है, तो इससे न केवल बांग्लादेश की लोकतांत्रिक साख प्रभावित होगी, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। भारत को इस पूरे घटनाक्रम में संयम, संतुलन और दूरदृष्टि के साथ आगे बढ़ना होगा। न तो उसे किसी आंतरिक राजनीतिक विवाद का पक्षकार बनना चाहिए और न ही लोकतांत्रिक मूल्यों की उपेक्षा करनी चाहिए। भारत की विदेश नीति का मूल उद्देश्य एक स्थिर, शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और समृद्ध पड़ोस होना चाहिए। यही उसकी सुरक्षा, आर्थिक प्रगति और क्षेत्रीय नेतृत्व के लिए सबसे अनुकूल स्थिति होगी। भौगोलिकसंदर्भ

आज आवश्यकता किसी राजनीतिक विजय की नहीं, बल्कि राजनीतिक परिपक्वता की है। बांग्लादेश को यह सिद्ध करना होगा कि लोकतंत्र केवल चुनाव का नाम नहीं, बल्कि विपक्ष के सम्मान, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और राजनीतिक सहिष्णुता का भी नाम है। वहीं भारत को यह दिखाना होगा कि वह पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को व्यक्तियों के बजाय संस्थागत विश्वास, पारस्परिक सम्मान और साझा हितों के आधार पर आगे बढ़ाने में सक्षम है। दिसंबर 2026 में यदि शेख हसीना वास्तव में बांग्लादेश लौटती हैं, तो वह केवल एक नेता की वापसी नहीं होगी, वह बांग्लादेश के लोकतंत्र, भारत की कूटनीतिक परिपक्वता और दक्षिण एशिया की राजनीतिक स्थिरता की एक साथ परीक्षा होगी। यदि इस चुनौती को संवाद, लोकतांत्रिक मर्यादा और विवेकपूर्ण कूटनीति के साथ संभाला गया, तो यह संकट दोनों देशों के संबंधों में एक नए विश्वास और नई शुरुआत का आधार भी बन सकता है। यही समय की सबसे बड़ी मांग है। यहां एक बड़ा प्रश्न यह भी है कि शेख हसीनाा के बांग्लादेश यानी वतन-वापसी से वहां राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को नई धार मिलेगी या फिर वह और अधिक बंट जाएंगी?

धर्म बदला तो बेटियों को किया कैद, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिलाई आजादी, अब पिता और यूपी सरकार को देना होगा 25 लाख

बालिग बेटियों की जबरन कैद पर HC सख्त

आर्यावर्त संवाददाता

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बालिग बेटियों को जबरदस्ती अवैध कैद में रखने से जुड़े मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और बेटियों के पिता दोनों को पीड़ित बेटियों को 25 लाख का देने का आदेश दिया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर जस्टिस संदीप जैन ने ये फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोनों बेटियों को उनकी मर्जी के मुताबिक किसी भी स्थान पर रहने और अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ जीवन जीने की पूरी आजादी प्रदान की है आइये जानते हैं क्या है पूरा मामाला।

दरअसल दो सगी बहनों ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की थी। दोनों ने धर्म परिवर्तन किया है। उन्होंने हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म को अपनाया था। आगरा के सदर बाजार क्षेत्र निवासी अनिल कुमार भाटिया की दो बेटियों अंशु भाटिया उर्फ अमीना और दिया भाटिया उर्फ ज़ोया ने कोर्ट के सामने पेश समक्ष होकर स्पष्ट तौर पर कहा कि उन्होंने साल 2020 और 2021 में बिना किसी डर, लालच, दबाव या जबरदस्ती के अपनी मर्जी और आत्मिक शांति के लिए इस्लाम धर्म अपनाया था।

धर्म परिवर्तन के बाद उनके पिता ने उन्हें घर के अंदर जबरन अवैध रूप से बंधक बना लिया। उनके शैक्षणिक दस्तावेज, पासपोर्ट, बैंक पासबुक और पहचान पत्र जब्त कर लिए और उन पर धर्म वापस बदलने के लिए शारीरिक एवं मानसिक दबाव बनाया।

इसके साथ ही पिता ने आगरा के सदर बाजार थाने में जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था, जिसमें बाद में BNS की धाराएं और यूपी धर्मांतरण रोधी

अधिनियम 2021 की धाराएं जोड़ी गई थीं। राज्य सरकार की तरफ से तर्क दिया गया कि यह एक संगठित साजिश का हिस्सा हो सकता है।

कोर्ट ने बेटियों को रिहा करने का दिया आदेश

वहीं कोर्ट ने राज्य सरकार के तर्कों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि दो बालिग लड़कियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वेच्छा से धर्म चुनने के अधिकार को महज आशंकाओं के आधार पर छीना नहीं जा सकता। कोर्ट ने दोनों लड़कियों को फौरन रिहा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि वो अपनी इच्छा से कहीं भी रहने और किसी भी व्यक्ति के साथ जाने के लिए स्वतंत्र हैं।

कोर्ट ने क्या कहा

जस्टिस संदीप जैन ने अपने 70 पेज के विस्तृत आदेश में स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत स्वायत्तता सर्वोपरि है। संविधान का अनुच्छेद 21 (जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 25 (धर्म और अंतःकरण की स्वतंत्रता) प्रत्येक बालिग नागरिक को अपनी पसंद का धर्म चुनने और अपनी मर्जी से रहने का अखंडनीय अधिकार देता है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी पिता अपनी बालिग संतान को सिर्फ इसलिए घर में कैद नहीं कर सकता कि वह उसके धार्मिक विचारों या व्यक्तिगत निर्णयों से असहमत है। बालिग होने पर पारिवारिक अधिकार संवैधानिक स्वतंत्रता के आगे समाप्त हो जाता है। कोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस तंत्र के रवैये पर भी गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की बजाय पुलिस ने पीड़िता को राहत देने में उदासीनता बरती और अवैध हिरासत को जारी रहने दिया।

25 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश

कोर्ट ने कहा कि पिता और राज्य सरकार 8 सप्ताह के अंदर दोनों बहनों को बराबर-बराबर (12.15-12.15 लाख रुपये) कुल 25 लाख रुपये का मुआवजा दे। राज्य सरकार मुआवजा राशि चुकाने के बाद 50 प्रतिशत राशि पिता से और शेष 50 प्रतिशत राशि उन दोषी पुलिस/सार्वजनिक अधिकारियों से वसूलने के लिए स्वतंत्र होगी, जिनकी लापरवाही से युवतियों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ। कोर्ट ने पिता को आदेश दिया गया है कि बेटियों के सभी मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, बैंक पासबुक और अन्य दस्तावेज सात दिन के भीतर उन्हें सौंपें। साथ ही पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि बेटियों के शांतिपूर्ण जीवन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न होने दें और जरूरत पड़ने पर उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करें।

पति की मौत के बाद अगर पत्नी ने बच्चा गोद लिया तो उसकी संपत्ति पर किसका हक? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि पति की मौत के बाद अगर कोई विधवा किसी बच्चे को गोद लेती है तो वो बच्चा मृतक पति का भी गोद लिया हुआ बेटा माना जाएगा और उसे पति का हिस्सा मिलेगा। उसे पति की संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। जस्टिस चंद्र कुमार राय ने यह फैसला प्रयागराज के राम कृपाल द्वारा 1983 में दायर याचिका खारिज करते हुए सुनाया। दरअसल राम कृपाल ने अपनी याचिका में चकबंदी (कंसोलिडेशन) अधिकारी के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें मोती रानी और उनके दिवंगत पति मुरलीधर के गोद लिए हुए बेटे रामजी को मुरलीधर की संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार दिया गया था। रामजी का नाम गांव रसौली के खाता नंबर 96 पर मुरलीधर के गोद लिए हुए बेटे के तौर पर दर्ज था। जानकारी के मुताबिक मुरलीधर की मौत हो गई थी और उनकी कोई संतान नहीं थी। मुरलीधर की मौत के बाद पत्नी उनकी संपत्ति का हिस्सा उनकी पत्नी मोती रानी को मिला। रामजी ने दावा किया कि मोती रानी ने दो अगस्त 1960 को उन्हें विधिवत तरीके से गोद लिया था।

पहली तीन संतानों पर नहीं ली छुट्टी, तो क्या चौथी पर मिलेगी मैटरनिटी लीव? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला

आर्यावर्त संवाददाता

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि अगर किसी सरकारी सेवक महिला की दो या अधिक जीवित संतानें हैं, तो वह मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) के लिए पात्रता नहीं होगी, भले ही वह किसी विशेष प्रसव के लिए पहली बार यह अवकाश मांग रही हो। यह आदेश जस्टिस मंजू रानी चौहान की सिंगल बेंच ने शशि कुमारी की याचिका पर दिया है।

जानकारी के मुताबिक याचिकाकर्ता ने 19 जून 2026 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके चौथे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश की मांग को खारिज कर दिया गया था। याचिका में यह भी मांग की गई थी कि विभाग को छह माह का मातृत्व अवकाश देने का निर्देश दिया जाए।

याचिकाकर्ता का तर्क

याचिकाकर्ता की तरफ से उनके वकील ने तर्क दिया कि उन्होंने पहली तीन संतानों के जन्म पर कोई अवकाश नहीं लिया था। चूंकि चौथी संतान के लिए पहली बार वह यह लाभ ले रही है, इसलिए इनकार करने का आदेश मनमाना और कानून की दृष्टि से गलत है।

राज्य ने क्या कहा

वहीं राज्य की तरफ से कहा गया कि याचिकाकर्ता पहले ही मतृत्व अवकाश ले चुकी है। कोर्ट में यह जानकारी दी कि वित्तीय हस्त पुस्तिका के खंड-II, भाग 2 से 4 (अध्याय-10) के प्रावधानों के अनुसार प्रसूती अवकाश प्रसव की तिथि से 180 दिनों तक स्वीकृत किया जाता है। यह अवकाश तभी दोबारा मिल सकता है जब पिछले स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के दो वर्ष बीत चुके हों। सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि अगर किसी महिला सरकारी सेवक की दो या अधिक जीवित संतानें हैं, तो उसे प्रसूति अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता, चाहे यह अवकाश अन्यथा देय क्यों न हो।

गर्भपात के मामलों में अवकाश का प्रावधान

साथ ही गर्भपात के मामलों के लिए अलग से 6 सप्ताह के अवकाश का प्रावधान है, जिस पर पहले तीन बार की सीमा 1990 की एक अधिसूचना से पहले ही हटाई जा चुकी है। कोर्ट ने कहा कि याचिका के साथ मूल दस्तावेजों की फोटोस्टेट प्रतियां नहीं लगाई गई थीं, बल्कि केवल टाइप की गई प्रतियां संलग्न थीं, जिनमें टाइपिंग की त्रुटियां पाई गईं।

संक्षेप

गर्भपात के बाद महिला की मौत, अस्पताल सील

सुल्तानपुर। कादीपुर में कथित अवैध तरीके से कराए गए गर्भपात के बाद 27 वर्षीय महिला की मौत हो गई। महिला की मौत से नाराज परिजनों ने शव सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया। मृतका की पहचान गुड़िया निषाद, निवासी सरैया मुस्तफाबाद के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक गुड़िया करीब तीन माह की गर्भवती थी। आरोप है कि कुछ दिन पहले शांति उर्फ बुआ ने सरैया बाजार स्थित एक निजी क्लीनिक में उसका गर्भपात कराया था। गर्भपात के बाद 8 अगस्त को गुड़िया की तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे लखनऊ के ट्रामा सेंटर ले गए, जहां 10 अगस्त की सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में परिजनों की तहरीर पर कादीपुर पुलिस ने शांति उर्फ बुआ और भीम चरन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सीएमओ के निर्देश पर गठित चिकित्सकों की टीम ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में विमला हॉस्पिटल को सील कर दिया। सीओ कादीपुर विनय गौतम के मुताबिक आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतका अपने पीछे चार साल के बेटे को छोड़ गई है।

कावड़ियों के लिए भव्य भंडारे का आयोजन

जौनपुर । सुजानगंज क्षेत्र के इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के बगल सावित्री मैरिज हॉल के सामने बाबा सिद्धार्थ गौतम भगवान राम सेवा समिति भलुआही बदलापुर द्वारा बोल बम भक्तों के लिए किया गया भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। कावड़िया के स्वागत के लिए और उनके खान-पान की व्यवस्था के लिए वृहद भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें भंडारे में फल से लेकर पुरी सब्जी खीर बूंदी पानी उपचार हेतु दवा की व्यवस्था किया गया था। भंडारा 2 बजे रात तक चलता रहा भंडारे का आयोजक रत्नेश कुमार दुबे ,द्वारा किया गया । दीपक कुमार जायसवाल, श्याम नारायण विश्वकर्मा, आर्यन सिंह, नरेंद्र शर्मा, रामसूरत, डॉक्टर अशोक ,बसंत, गुड्डू प्रजापति आदि ने भंडारे को सफल पूर्वक चलाया ।

राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान का लिया संकल्प

जौनपुर। परिषदीय विद्यालयों में 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत मंगलवार को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन उत्साह और देशभक्ति के माहौल में किया गया। कार्यक्रमों में छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी रचनात्मक प्रतिभा के जरिए राष्ट्रप्रेम की अनूठी झलक पेश की। विद्यालयों में बच्चों ने तिरंगे झंडे तैयार करने के साथ ही तिरंगा रंगोली, फूल-पत्तियों से आकर्षक रंगोली, कला एवं चित्रकला तथा मेहंदी प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया। तिरंगे के तीन रंगों से सजी रंगोलियां और विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई कलाकृतियां विद्यालय परिसरों में आकर्षण का केंद्र रहीं। बच्चों में खासा उत्साह नजर आया। छात्र-छात्राओं ने अपनी प्रस्तुतियों और रचनात्मक कार्यों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, अखंडता और तिरंगे के प्रति सम्मान का संदेश दिया। शिक्षकों ने विद्यार्थियों को राष्ट्रीय ध्वज के महत्व, उसके सम्मान और देश के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों की जानकारी दी। 'हर घर तिरंगा' अभियान के जरिए बच्चों को देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना से जोड़ने का प्रयास किया गया।

बीएससी पाठ्यक्रम में रिक्त सीटों पर सीधे प्रवेश

जौनपुर। पूर्वांचल विश्वविद्यालय परिसर में शैक्षणिक सत्र के लिए बीएससी पाठ्यक्रम के में प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थियों के सीधे प्रवेश ले सकते है। यह प्रवेश पहले आओ पहले पाओगे आधार पर होगा। इंटरमीडिएट जीव विज्ञान या गणित से परीक्षा उत्तीर्ण ऐसे विद्यार्थी, जो बीएससी में प्रवेश लेना चाहते हैं, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पात्रता एवं प्रवेश संबंधी नियमों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश सीटों की उपलब्धता एवं निर्धारित मानकों के आधार पर किया जाएगा। प्रो मिथिलेश सिंह के अनुसार प्रवेश से संबंधित पात्रता, विषय संयोजन, शुल्क, आवश्यक दस्तावेज तथा अंतिम तिथि की जानकारी विश्वविद्यालय की आधिकारिक सूचना एवं संबंधित विभाग से प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रिया कर सकते है।

वितरण किया गया विभागों को राष्ट्रीय ध्वज

जौनपुर । स्वतंत्रता दिवस के पूर्व जनपद में राष्ट्रीय पर्व की भावना को जन-जन तक पहुंचाने तथा 'हर घर तिरंगा अभियान' को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ध्वज वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी सहित विकास भवन एवं अन्य विभागों में जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी सतीश चंद्र गुप्ता द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राष्ट्रीय ध्वज वितरित किए गए। विभाग द्वारा वित्तपोषित इकाइयों एवं संबंधित प्रतिष्ठानों को भी अपने-अपने घरों एवं प्रतिष्ठानों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने के लिए प्रेरित किया गया। अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान एवं गौरव की भावना व्यक्त करते हुए आमजन को भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया।

गोमतेश्वर महादेव मंदिर में पानी भरा

जौनपुर । गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने से गोमतेश्वर महादेव मंदिर में पानी भर गया है। सावन माह में नदी के जल से भगवान शिव का जलाभिषेक हो रहा है। घुटनों तक पानी होने के बावजूद श्रद्धालु पूजन और जलाभिषेक कर रहे हैं। यद्यपि गोमती नदी का जलस्तर अभी खतरे के निशान से काफी नीचे है। जलस्तर में वृद्धि के कारण नदी के तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। संभावित बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिले में 347 गांवों को बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील चिह्नित किया गया है। इन गांवों की निगरानी के लिए 58 बाढ़ चैकियां स्थापित की गई हैं। सभी तहसीलों के उप जिलाधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। गोमती के साथ-साथ सई, पीली और वरुणा नदियों के जलस्तर पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। राहत और बचाव कार्यों के लिए जिले में कुल 42 गोताखोरों की व्यवस्था की गई है। इन गोताखोरों में सदर में 12, मड़ियाहूं में पांच, मछलीशहर में दो, शाहगंज में चार, केराकत में तीन और बदलापुर में 12 गोताखोर तैनात किए गए हैं।

इमाम हसन की शहादत पर निकाला जुलूस

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। मुसलमानों के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा और उनके बड़े नवासे दूसरे इमाम इमाम हसन की शहादत की याद में सोमवार रात्रि में शबे 27 सफर का जुलूस स्थान हुसैनिया नकी फाटक से उठा, जो देर रात संपन्न हुआ। जुलूस में अन्जुमनो ने हाय रसूले खुदा, हाय इमामे हसनष नौहा पढ़ा व मातम किया और रसूल व इमाम की शहादत पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान भारी संख्या में महिला पुरूष व बच्चो ने भाग लिया। नकी फाटक में मजलिस हुई जिसमें सोजख्वानी अब्बास काजमी ने अपने साथियों के साथ किया। मजलिस को धर्म गुरु मौलाना महफूजुल हसन खां ने कहा कि कि मोहम्मद साहब ने खुदा के पैगाम को पूरी दुनिया तक पहुँचाया। मजलूमों, गुलामों, औरतों, बेसहारा व यतीमों को उनका हक दिलाया। मोहम्मद साहब ने इंसानों को मानवता का पाठ पढ़ाते हुए सच्चाई की राह पर चलने व अमन शान्ति का संदेश दिया। इस्लाम धर्म सबको समानता का अधिकार दिलाने का पैगाम देता है। शहर की अन्जुमने जुल्फेकारिया बड़ी मस्जिद, अजादारिया बारादुअरिया, कौसरिया रिजवी खा व असगरिया पुरानी बाजार ने नौहा पढ़ती-मातम करती हुई जुलूस की शक्ल मे मल्हनी पड़ाव होते हुए इमाम चैक वक्फ बीकानी बीबी डढ़यिाना टोला तक गई। जुलूस पुनः नकी फाटक मे आकर संपन्न हुआ।

जफराबाद में निकाली गई तिरंगा यात्रा

जौनपुर। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मंगलवार को नगर पंचायत जफराबाद मे एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई।यह यात्रा हरगोविंद इंटर कॉलेज जफराबाद से प्रारंभ होकर कस्बे में होते हुए शहीद स्मारक हौज तक पहुंची। वरिष्ठ नेता एवं उद्योगपति ज्ञान प्रकाश सिंह के नेतृत्व में निकली इस तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, समर्थक और हरगोविंद इंटर कालेज के छात्र छात्राएं व स्थानीय लोग शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर लोगों ने देशभक्ति के नारों के साथ स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को नमन किया।इस अवसर पर ज्ञान प्रकाश सिंह ने कहा कि यह तिरंगा यात्रा केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश के प्रति सम्मान और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि अभी तो यह शुरुआत है, आने वाले समय में देशहित और समाजसेवा से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जाए ।

खुदीराम बोस को शहादत दिवस पर दी श्रद्धांजलि

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। भारतीय आजादी आंदोलन के महान क्रांतिकारी, देश के पुष्प, अमर शहीद खुदीराम बोस की 118वीं शहादत दिवस के अवसर काकोरी ऐक्शन शताब्दी वर्ष आयोजन समिति के तत्वावधान में श्री बद्रीनाथ शिक्षण संस्थान मल्लूपुर, बदलापुर, में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। समिति के जिला उपाध्यक्ष दिलीप कुमार ने कहा कि, क्रूर अंग्रेज मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की बघ्घी पर बम फेकने के खिलाफ जब खुदीराम बोस को अदालत में फाँसी की सजा सुनाई जा रही थी तो वे घबराये नहीं, बल्कि मजिस्ट्रेट के सामने मुस्करा रहे थे और जैसे कह रहे हों कि, तुम मुझे मार सकते हो लेकिन मेरे विचारों को नहीं। इस तरह खुदीराम बोस सीना तानकर फांसी घर की ओर बढ़ चले और मात्र 19 साल से कम उम्र में फांसी के फंदे चूम कर वे शहीद हो

गये। लेकिन अफसोस कि! आजादी 78 सालों के बाद भी उनके जैसे अनगिनत क्रांतिकारियों के सपने आज भी अधूरे हैं। आज देश भर में शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सम्मान सहित जीवन के हर क्षेत्र में चैतरफा संकट व्याप्त है। कार्यक्रम को प्रधानाचार्य एसपी यादव ने भी संबोधित किया। संचालन- संतोष कुमार प्रजापति ने किया। शोभनाथ यादव, विकास मौर्य, सुनील मौर्य, मोनू उपाध्याय, श्रद्धा यादव, सोनी शर्मा, शिक्षा मौर्य सहित अन्य कई लोग मौजूद रहे।

यूपी में प्राइमरी शिक्षा के फंड में 843 करोड़ की कटौती, राजस्थान-मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक किसे कितना पैसा मिला?

आर्यावर्त संवाददाता

बरेली। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा से जुड़े खर्च के लिए मिलने वाले फंड में कमी आई है।। केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में 10 अगस्त 2026 को दिए गए एक सवाल के जवाब के मुताबिक समग्र शिक्षा के तहत एलीमेंट्री यानी प्राइमरी एजुकेशन के लिए राज्यों को दिए गए फंड में उत्तर प्रदेश को 2025-26 में 9,742.12 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। अब 2026-27 में घटकर 8,898.96 करोड़ रुपये रह गए। इसका साफ अर्थ यह एक साल प्राइमरी एजुकेशन के लिए उत्तर प्रदेश को मिलने वाले फंड में तकरीबन 843 करोड़ रुपये की कमी आई है।

यूपी में समग्र शिक्षा के तहत एलीमेंट्री एजुकेशन के लिए आवंटन में उतार-चढ़ाव रहा है। 2023-24 में राज्य को 10,082.90 करोड़ रुपये आवंटित हुए थे। 2024-25 में यह

राशि घटकर 9,600.34 करोड़ रुपये हुई। इसके बाद 2025-26 में मामूली बढ़ोतरी के साथ आवंटन 9,742.12 करोड़ रुपये हुआ। अब 2026-27 में यह फिर घटकर 8,898.96 करोड़ रुपये रह गया है। साल 2023-24 के मुकाबले 2026-27 में यूपी के लिए यहआवंटन करीब 1,184 करोड़ रुपये कम है।

यूपी के अलावा अन्य किन राज्यों को प्राइमरी एजुकेशन को मिलने वाला फंड घटा

सिर्फ यूपी ही नहीं, बिहार, राजस्थान, आंध्र में एलीमेंट्री एजुकेशन तहत मिलने वाले फंड में कमी

बिहार में 2025-26 में 7,283.43 करोड़ रुपये आवंटित हुए थे।

बिहार को 2026-27 में मिलने वाली यह राशि घटकर 5,970.76 करोड़ रुपये हो गई।

इसका साफ अर्थ है कि बिहार को मिलने वाले इस राशि में 1,313 करोड़ रुपये की कमी।

राजस्थान को भी 2025-26 में 4,010.56 करोड़ रुपये के मुकाबले 2026-27 में 3,081.48 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

आंध्र प्रदेश में भी फंड 1,642.42 करोड़ रुपये से घटकर 1,145.26 करोड़ रुपये रह गया है।

किन राज्यों के एलीमेंट्री एजुकेशन के फंड में हुई बढ़ोतरी?

हालांकि कई राज्यों में एलीमेंट्री यानी प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के खर्च के लिए मिलने वाले फंड में बढ़ोतरी भी हुई है। 2025-26 में मध्य प्रदेश के लिए 3,855.82 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जो 2026-27 में बढ़कर 4,087.96 करोड़ रुपये हो गए। गुजरात में भी फंड 1,588.69 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,895.02 करोड़ रुपये हुआ है। पश्चिम बंगाल में 1,799.88 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,141.38 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

तमिलनाडु में भी 1,936.42 करोड़ रुपये के मुकाबले इस साल 2,059.44 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है।कर्नाटक में फंड 1,480.27 करोड़ रुपये से घटकर 1,359.25 करोड़ रुपये हुआ है। महाराष्ट्र में 2025-26 में 1,681.91 करोड़ रुपये के मुकाबले 2026-27 में 1,744.65 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं।

राज्यों के प्राइमरी एजुकेशन के लिए फंड तय करने का आधार क्या?

केंद्र सरकार के मुताबिक समग्र शिक्षा के तहत प्राथमिक शिक्षा में खर्च के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से उनकी जरूरत और प्राथमिकताओं के आधार पर वार्षिक कार्ययोजना और बजट तैयार किया जाता है। इसके बाद प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड राज्यों के साथ चर्चा करके योजना का आकलन किया जाता है, फिर फंड को अप्रूवल मिलता है। फंड जारी करते समय सिर्फ अप्रूव्ड राशि ही नहीं देखी जाती, बल्कि राज्य की खर्च करने की गति, राज्य के हिस्से की राशि, ऑडिटेड अकाउंट, पिछले साल की उपयोगिता प्रमाणपत्र और बची हुई राशि जैसे पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाता है। सरकार ने अपने जवाब में यह भी कहा है कि कुछ राज्य खर्च की धीमी रफ्तार के कारण सभी किस्तें हासिल नहीं कर पाते।

अगर राज्य के पास पिछले साल की राशि बची हुई है, तो उस अनस्पेंट बैलेंस को भी अगली बार फंड जारी करते समय ध्यान में रखा जाता है। मतलब सरकार का तर्क है कि पहले से पैसा बचा है तो तुरंत उतनी ही अतिरिक्त राशि देने की जरूरत कम हो सकती है।

फंड जारी करने से पहले केंद्र यह भी देखता है कि राज्य ने अपने हिस्से की राशि दी है या नहीं। इसके अलावा ऑडिटेड अकाउंट, पिछले साल का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट(UC) और खर्च का अपडेटेड स्टेटमेंट भी जरूरी होता है।

स्कूलों में किन कामों पर खर्च होता है पैसा?

2025-26 में इस योजना के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2,871.95 करोड़ रुपये खर्च किए गए

शिक्षकों के वेतन पर 13,508.169 करोड़ रुपये खर्च किए गए

मुफ्त किताबों पर 2,353.23 करोड़ रुपये और मुफ्त यूनिफॉर्म पर 3,871.02 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

फंड की कटौती में सिर्फ केंद्र का नहीं यूपी सरकार का भी हो सकता है रोल

उत्तर प्रदेश में समग्र शिक्षा के तहत एलीमेंट्री एजुकेशन के लिए 2026-27 में करीब 843 करोड़ रुपये का कम आवंटन हुआ है। लेकिन उपलब्ध सरकारी जवाब से यह नहीं कहा जा सकता कि इस कमी की कोई एक खास वजह है या सिर्फ केंद्र ने फंड में कटौती की है। यह भी हो सकता है कि राज्य सरकार ने इतने ही बजट की कार्ययोजना को केंद्र सरकार के पास भेजा है।

न बातचीत, न इमोशन, एक ही घर में सब अनजान...रील्स देखने की लत से रिश्तों को कितना नुकसान

लोग रील्स, शॉर्ट्स या वीडियो को देखने के लिए इस कदर बिजी हैं कि उनकी लाइफ अब पहले जैसी नॉर्मल नहीं है . रील्स की लत क्यों पड़ती है और ये कैसे रिश्तों में दूरी ला रही है एक्सपर्ट से जानें...

रील्स की लत...। आज ये अमूमन भारत के हर घर की समस्या बन गई है। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक, किसी भी टाइम लोग कई घंटे रील्स देखने में लगे रहते हैं। ये हमें मेंटली तो कमजोर बना रही है पर ये कैसे रिश्तों में दूरी ला रही है, ये बहुत कम समझ पा रहे हैं। एक इंसान जब रील्स देखने लगता है तो वो अपनी ही दुनिया में खो जाता है। एनसीबीआई की रिपोर्ट कहती है कि रील्स की लत से दिमाग और शरीर दोनों पर बुरा असर पड़ता है। लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आंखों की रोशनी कमजोर, फिजिकली फिट न होने से मोटापा और डायबिटीज जैसी बीमारियां हो सकती हैं।

इन सब में एक बड़ा खतरा रिश्ते को खोना या इनमें आने वाली दूरी है। एक ही घर में अनजानों की तरह रहना, न बातचीत और न ही इमोशन्स होना... ऐसी कई दिक्कतें हैं जो लोगों को अपनों से अलग कर रही हैं। चलिए आपको एक्सपर्ट के जरिए बताते हैं...

रील्स का नशा क्यों लगता है?

कई रिसर्च में सामने आया है कि हर कुछ सेकंड में नए वीडियो से दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। इस कंडीशन को Variable Reward System पुकारा जाता है। दरअसल, एक वीडियो के बाद दूसरी वीडियो में और भी मजेदार कंटेंट मिलेगा ये दिमाग में उम्मीद बनी रहती है। इसलिए लोग 10 मिनट की रील्स के टाइम में एक या दो घंटे तक बिता देता है। ये ही रील्स का नशा है।

हर रील में नयापन बनता है मुसीबत

डॉ। पंकज कुमार (प्रिंसिपल कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, मैक्स हॉस्पिटल) कहते हैं कि रील्स हमारे जीवन में बहुत कॉमन हो गई है। किसी भी उम्र का इंसान रील्स को देखते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि रील्स की लत जब पड़ जाती है तो इसका नुकसान हमारे रिश्तों को होता है। कुछ सेकंड में नया कंटेंट और तुरंत मिलने वाला डोपामाइन रिवॉर्ड देती है। ऐसे में हमारा दिमाग उतनी तेजी का आदी हो जाता है और इसी तरह रिश्तों में भी व्यवहार आने लगता है। बाद में परिवार के लोगों की बात उतनी रोचक नहीं लगती।

क्या होती है Phubbing?

रील्स की तरह रियल लाइफ इतनी फास्ट नहीं होती। रील्स में हर 30 सेकंड में नयापन आता है लेकिन रियल लाइफ में ऐसा संभव नहीं है। इसलिए असल जिंदगी हमें बोरिंग लगने लगती है। इस तरह की कंडीशन से रिश्तों में Phubbing बढ़ती है। इसका मतलब है कि सामने बैठे व्यक्ति को नजरअंदाज कर मोबाइल चलाना।

इमोशनल दूरी होना

आज कई घरों में लोग एक ही कमरे में फिजिकली बैठे तो होते हैं लेकिन उनके हाथों में मौजूद मोबाइल ही उनकी असली दुनिया होता है। एक्सपर्ट कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि साथ होते हुए भी भावनात्मक दूरी बढ़ जाती है। संवाद कम हो जाता है और इससे गलतफहमियां बढ़ जाती हैं।

अकेलेपन की शुरुआत होना

इतना ही नहीं कंडीशन अकेलेपन तक पहुंच जाती है। दिमाग में ख्याल आने लगते हैं कि मुझे कोई समझता नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। दरअसल, रील्स हमें उसी तरह का कंटेंट दिखाता है जिसकी हम ख्वाहिश रखते हैं। ऐसे में मन के अंदर उम्मीदें बढ़ जाती हैं और लोग अपनों से भी उम्मीदें बांधने लगते हैं। ऐसे में उनसे मनमुटाव होता है और इंसान अकेलेपन में अपनी ही दुनिया बनाने लगता है।

खतरे की घंटी तब बजती है जब इंसान हर सिचुएशन जैसे खाते समय, सोते समय, बातचीत के बीच और परिवार के साथ बिताया हुआ समय उसे बोर लगने लगे। अपनों को ही टॉक्सिक फील करने के हालात बनने लगते हैं।

एक्सपर्ट कहते हैं कि इसका सॉल्यूशन डिजिटल डिटॉक्स है। आपको पूरी तरह फोन को छोड़ना नहीं है बस इसे यूज करने की लिमिट तय करनी है।

घर में नो फोन टाइम तय कर सकते हैं। जैसे खाना खाते वक्त फोन को बिल्कुल नहीं छूना है।

सोने से अक्सर दो घंटे पहले फोन को नहीं छूना है क्योंकि इसकी ब्लू लाइट हमारी मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है।

परिवार के साथ कम से कम आधा घंटा जरूर बिताएं।

इसका सॉल्यूशन है डिजिटल डिटॉक्स

रोजाना गोमुखासन करने से मिल सकते हैं कई स्वास्थ्य लाभ

गोमुखासन को योग की सबसे प्रभावी मुद्राओं में से एक माना जाता है। इसका अभ्यास करने से कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। यहां हम आपको इस योगासन के बारे में विस्तार से बताएंगे और रोजाना इसे करने के फायदे भी बताएंगे। गोमुखासन का नाम 2 शब्दों से लिया गया है, जिसमें गौ का मतलब गाय और मुख का मतलब मुंह है। यह योगासन शरीर को ताकतवर और लचीला बनाने में मदद कर सकता है।

गोमुखासन करने का तरीका

सबसे पहले जमीन पर सीधे बैठें और अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं घुटने के ऊपर से इसके किनारे जमीन पर रखें। इसी तरह अपने बाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं घुटने के ऊपर से इसके किनारे जमीन पर रखें।

अब अपने दोनों हाथों को कोहनी से मोड़ते हुए पीठ के पीछे आपस में पकड़ने का प्रयास करें। इस मुद्रा में कुछ मिनट रहने के बाद धीरे-धीरे सामान्य हो जाएं।

पीठ की समस्याओं से मिलेगा छुटकारा

गोमुखासन का नियमित अभ्यास पीठ की समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है। यह योगासन पीठ के निचले हिस्से, कंधों और गर्दन की मांसपेशियों को मजबूती देता है।

इसके अलावा यह योगासन रीढ़ की हड्डी को भी स्वस्थ रखता है। अगर आपको पीठ में दर्द की समस्या रहती है तो रोजाना इस योगासन का अभ्यास जरूर करें।

इससे आपकी पीठ मजबूत बनेगी और दर्द से राहत भी मिलेगी।

पाचन क्रिया को कर सकता है दुरुस्त

गोमुखासन पाचन क्रिया के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसका नियमित अभ्यास पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और पाचन क्रिया को सुधारता है।

इससे कब्ज और गैस जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। इसके अलावा यह योगासन पेट की अंदरूनी सफाई भी करता है और रक्त के प्रवाह को बेहतर बनाता है।

अगर आप रोजाना गोमुखासन करते हैं तो आपकी पाचन क्रिया स्वस्थ रहती है और पेट संबंधी समस्याओं से दूर रहते हैं।

प्रदान करता है मानसिक शांति

गोमुखासन मानसिक शांति प्रदान करने में भी मददगार है। यह योगासन दिमागी तनाव को कम करता है और मन को शांत रखता है।

इसके नियमित अभ्यास से ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ती है और मानसिक स्पष्टता मिलती है। गोमुखासन करने से आप अधिक सतर्क और केंद्रित महसूस करते हैं, जिससे आपकी उत्पादकता भी बढ़ती है।

यह योगासन मानसिक संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है, जिससे आप अधिक शांत और खुश रहते हैं।

सांस संबंधी समस्याओं को करता है दूर

गोमुखासन सांस संबंधी समस्याओं, जैसे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस आदि में भी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस योगासन का नियमित अभ्यास फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है और सांस लेने की प्रक्रिया को सुधारता है।

गोमुखासन करने से श्वसन तंत्र मजबूत होता है, जिससे ऑक्सीजन का बेहतर उपयोग होता है।

इसके अलावा यह योगासन श्वसन नलियों को खोलता है और फेफड़ों की कार्यक्षमता को सुधारता है, जिससे सांस संबंधी समस्याओं में राहत मिलती है।

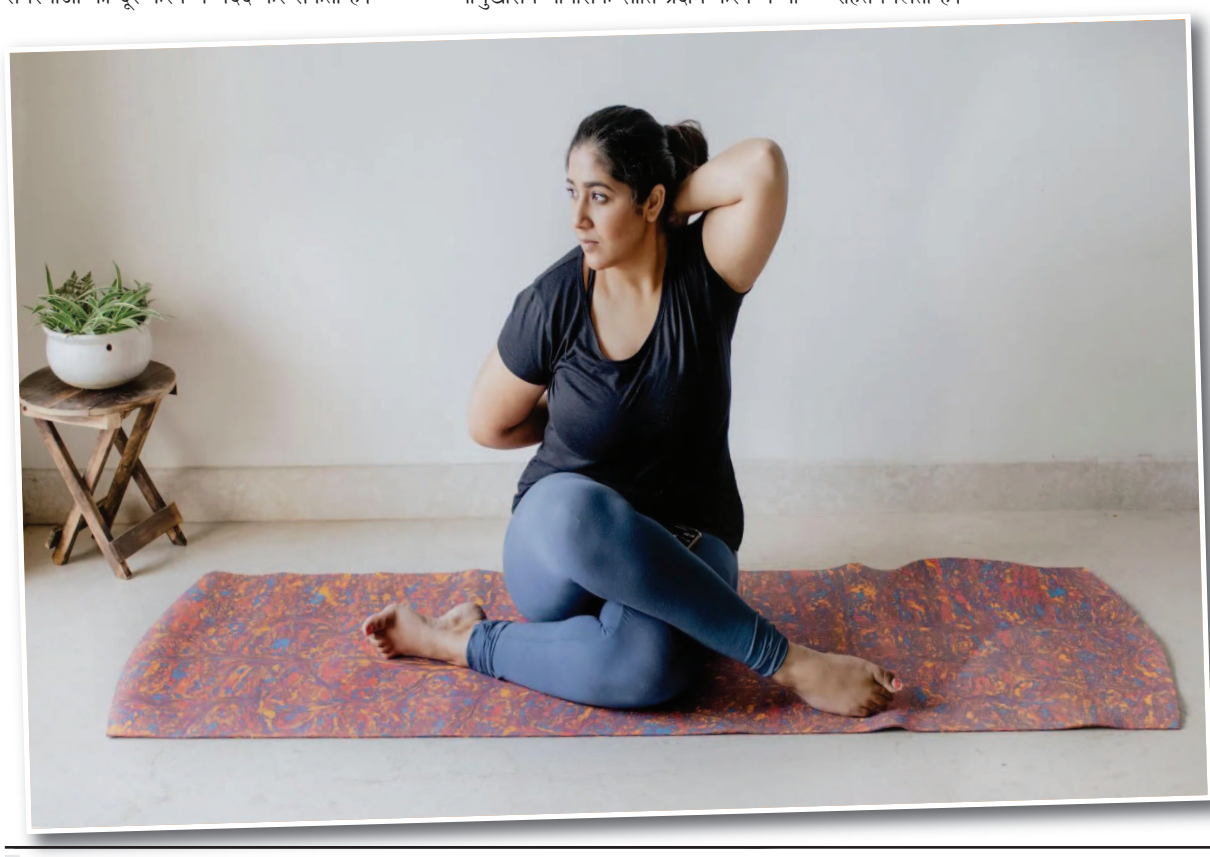

भारत में 35 फीसदी बच्चों को फैटी लिवर? ऐसा क्यों हो रहा है? कैसे करें बचाव

भारत तेजी से बढ़ते लिवर स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है। नए महामारी-संबंधी डेटा से पता चलता है कि फैटी लिवर की बीमारी अब देश भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रही है और पिछले दशक में इसके मामलों की दर तेजी से बढ़ी है। हाल ही में हुई वैश्विक और राष्ट्रीय हेल्थ रिसर्च से मिले इन रिजल्ट के आधार पर एक्सपर्ट्स जांच और रोकथाम के लिए तुरंत कदम उठाने की मांग कर रहे हैं।

डॉ। पीयूष विश्वकर्मा (कंसल्टेंट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, हेपेटोलॉजी एवं लिवर ट्रांसप्लांट आरजी हॉस्पिटल्स) बताते हैं कि फैटी लिवर बीमारी को अब ज्यादा सटीक रूप से MASLD (मेटाबोलिक डिसफंक्शन-एसोसिएटेड स्टेनोटिक लिवर डिजीज) कहा जाता है। इससे भारत की 16% से 32% आबादी के प्रभावित होने का अनुमान है। यह आंकड़ा लगभग 12 करोड़ लोगों के बराबर है।

क्या कहते हैं आंकड़े

जब इन आंकड़ों पर और गहराई से अध्ययन किया जाता है तो यह और भी चिंताजनक लगते हैं। 26,000 से ज्यादा लोगों पर की गई 50 स्टडी के विश्लेषण से पता चला है कि भारत में 38।6% वयस्कों को नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD) है। डायबिटीज या मोटापे से पीड़ित लोगों में यह दर (52।8%) और भी ज्यादा है। बच्चे भी इससे प्रभावित हैं। इसी विश्लेषण में पाया गया कि 35।4% बच्चों को फैटी लिवर की बीमारी है, और मोटापे से ग्रस्त बच्चों में यह आंकड़ा बढ़कर 63।4% हो जाता है।

आईटी सेक्टर में काम करने वालों पर खतरा ज्यादा

फैटी लिवर की बीमारी किसी को भी हो सकती है, चाहे वे कहीं भी रहते हों या कोई भी काम करते हों। स्टडी से पता चलता है कि भारत के IT सेक्टर में काम करने वाले लोगों को इसका ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि उन्हें लंबे समय तक बैठकर काम करना पड़ता है और उनकी लाइफस्टाइल की आदतें भी अस्वस्थ होती हैं। कर्नाटक और उत्तर भारत में हुई रिसर्च में भी शहरों और गांवों, दोनों जगहों पर इस बीमारी के ज्यादा मामले पाए गए। डायबिटीज, पेट के आसपास ज्यादा चर्बी और इंसुलिन रेजिस्टेंस इसके मुख्य जोखिम फैक्टर हैं।

हालांकि यह समस्या बड़े पैमाने पर फैली हुई है, लेकिन इस साल की शुरुआत में लिवर विशेषज्ञों के एक देशव्यापी सर्वे में बीमारी की पहचान और इलाज के तरीकों में कमियां पाई गईं। इससे पता चलता है कि फैटी लिवर की बीमारी के बढ़ते बोझ के हिसाब से हेल्थ केयर के तौर-तरीके अभी भी विकसित नहीं हो पाए हैं।

ये बीमारियां बनती हैं कारण

फैटी लिवर की बीमारी के बढ़ने के मुख्य कारणों में टाइप 2 डायबिटीज, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर और शारीरिक गतिविधि की कमी शामिल हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह एक मौका भी है, क्योंकि जिन लोगों की इनमें से किसी एक बीमारी के लिए जांच होती है, उनकी दूसरी बीमारियों के लिए भी जांच की जा सकती है।

इन चीजों का रखें ध्यान

हेल्दी लाइफस्टाइल में बदलाव, जैसे कि संतुलित डाइट खाना और नियमित रूप से एक्सरसाइज करना आदि उपाय एक ही समय में कई स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने में मदद कर सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले दशकों में फैटी लिवर बीमारी का बोझ लगातार बढ़ता जाएगा।

विदेशी मेहमानों के लिए भारत आना हुआ और आसान, सरकार ने खोले 11 नए इमिग्रेशन पॉइंट

पर्यटन, व्यापार और इलाज के लिए आने वाले विदेशी मेहमानों की राह अब और भी आसान हो गई है। ई-वीजा के जरिए अब 11 नई जगहों से भारत में एंट्री मिलेगी, जिससे देश में कुल 88 प्रवेश द्वार हो गए हैं।

95 प्रतिशत ई-वीजा आवेदनों को मात्र 72 घंटे में मंजूरी मिल रही है

भारत ने अपनी सीमाओं को वैश्विक यात्रियों के लिए और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्रालय ने विदेशी नागरिकों के लिए ई-वीजा (e-visa) नेटवर्क का दायरा बढ़ा दिया है। अब ई-वीजा पर सफर करने वाले यात्री 11 नए रास्तों से देश में कदम रख सकेंगे। इस फैसले के बाद भारत में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की एंट्री के लिए उपलब्ध पोर्ट्स की कुल संख्या बढ़कर 88 हो गई है। सरकार का ये कदम न केवल पर्यटन को नई रफ्तार देगा, बल्कि व्यापार, पढ़ाई और चिकित्सा के लिए भारत आने वाले लोगों की राह भी काफी आसान करेगा।

किन नए रास्तों से मिलेगी एंट्री?

सरकार की ओर से जारी की गई नई सूची में नौ जमीनी रास्ते (लैंड पोर्ट) और दो हवाई अड्डे शामिल किए गए हैं। जो लोग हवाई सफर के जरिए आना चाहते हैं, उनके लिए मध्य प्रदेश के भोपाल और आंध्र प्रदेश के तिरुपति एयरपोर्ट को इस विशाल नेटवर्क का हिस्सा बनाया गया है। वहीं, जमीनी रास्तों की बात करें तो भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थित अटारी के साथ-साथ दर्रांगा, गेदे, घोजाडंगा, हरिदासपुर, जयगांव, डौकी तथा मोरेह को इस लिस्ट में जगह मिली है।

यात्रा को आसान बनाने का विजन

इस बड़े विस्तार के बाद देश में कुल 88 अंतरराष्ट्रीय ई-वीजा एंट्री पॉइंट हो गए हैं। इनमें अब 37 हवाई अड्डे, 38 बंदरगाह और 13 जमीनी चेकपोस्ट शामिल हैं। गृह मंत्रालय का स्पष्ट कहना है कि इस फैसले का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक वीजा प्रणाली को विदेशी यात्रियों के लिए अधिक व्यावहारिक बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में पिछले कुछ वर्षों में वीजा नियमों को लगातार सरल किया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि भारत आने वाले वास्तविक यात्रियों को किसी भी तरह की कागजी परेशानी का सामना न करना पड़े।

डिजिटल बदलाव का शानदार असर

ई-वीजा के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस प्रणाली की सफलता साफ दिखाई देती है। मंत्रालय के अनुसार, ई-वीजा आवेदनों के निपटारे में अब काफी तेजी आई है। स्थिति यह है कि करीब 95 प्रतिशत आवेदनों को महज 72 घंटे के भीतर प्रोसेस कर दिया जाता है। यह डिजिटल बदलाव का ही नतीजा है कि आज भारत द्वारा जारी किए जाने वाले कुल वीजा में से 78 प्रतिशत हिस्सा ई-वीजा का है। भारत ने साल 2014 में सिर्फ 43 देशों के नागरिकों के लिए यह सुविधा शुरू की थी, जिसका दायरा आज 172 देशों तक फैल चुका है। फिलहाल पर्यटक, कारोबारी, छात्र और मेडिकल जैसी 17 अलग-अलग श्रेणियों में ई-वीजा जारी किया जा रहा है।

क्या आपके पसंदीदा रेस्टोरेंट में बरती जा रही है सफाई? सर्वे में आया डराने वाला आंकड़ा

जब भी हम परिवार के साथ बाहर खाना खाने की योजना बनाते हैं, तो सबसे पहले किसी अच्छे वातानुकूलित (एसी) रेस्टोरेंट का ही खयाल आता है। हम अक्सर यह मानकर चलते हैं कि एसी रेस्टोरेंट की शानदार सजावट और चमक-दमक के पीछे वहां परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और साफ-सफाई भी उतनी ही बेहतरीन होगी। लेकिन, हाल ही में हुए एक सर्वे ने इस धारणा को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है। लोकलसर्कल्स द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट ने देश भर के रेस्टोरेंट्स की असलियत को उजागर किया है। इस रिपोर्ट के आंकड़े इतने चिंताजनक हैं कि अगली बार बाहर खाना खाने से पहले आप गंभीरता से सोचने पर मजबूर हो जाएंगे।

91 हजार से अधिक ग्राहकों ने खोली हकीकत

यह सर्वे कोई छोटा-मोटा अध्ययन नहीं है, बल्कि इसमें भारत के 244 जिलों के 91,000 से अधिक ग्राहकों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सर्वे में शामिल होने वाले लोगों में 64 प्रतिशत पुरुष और 36 प्रतिशत महिलाएं थीं। यह अध्ययन देश के हर हिस्से तक पहुंचा, जिसमें 47 प्रतिशत लोग टियर-1 यानी बड़े शहरों से थे, 33 प्रतिशत टियर-2 शहरों से और बाकी 20 प्रतिशत लोग टियर-3 तथा टियर-4 वाले छोटे शहरों व कस्बों से थे।

जब इन ग्राहकों से पूछा गया कि उनके शहर के एसी रेस्टोरेंट में साफ-सफाई का स्तर कैसा है, तो केवल 32 प्रतिशत लोगों ने इसे 'अच्छा' या 'शानदार' बताया। इस 32 प्रतिशत में से भी मात्र 4 प्रतिशत को ही वहां की व्यवस्था 'शानदार' लगी, जबकि 28 प्रतिशत ने इसे सिर्फ 'अच्छा' कहा। वहीं, 42 प्रतिशत ग्राहकों ने सफाई व्यवस्था को केवल 'औसत' दर्जे का माना, जबकि 9 प्रतिशत लोगों का स्पष्ट कहना था कि यह 'खराब' या 'बहुत खराब' है।

किचन से लेकर डाइनिंग टेबल तक पसरी है गंदगी

सर्वे के दौरान ग्राहकों ने अपने जो निजी अनुभव साझा किए, वे सीधे तौर पर सेहत से खिलवाड़ की तरफ इशारा करते हैं। 57 प्रतिशत लोगों ने बताया कि उन्होंने खुद रेस्टोरेंट के डाइनिंग एरिया, किचन या वॉशरूम में काफी गंदगी देखी है। 53 प्रतिशत ग्राहकों ने वहां काम करने वाले कर्मचारियों को बेहद गंदे और असुरक्षित तरीके से खाना बनाते या परोसते हुए पाया। इतने ही यानी 53 प्रतिशत लोगों ने यह भी देखा कि खाना पकाने के लिए एक ही तेल को बार-बार इस्तेमाल किया जा रहा है।बात यहीं खत्म नहीं होती। 50 प्रतिशत ग्राहकों का अनुभव था कि उनका खाना ऐसे प्लास्टिक के बर्तनों में गर्म किया जा रहा था या परोसा जा रहा था, जो फूड-ग्रेड मानकों पर खरे नहीं उतरते और माइक्रोवेव के लिए सुरक्षित नहीं हैं। इसके अलावा, 45 प्रतिशत लोगों ने रेस्टोरेंट के अंदर कॉकरोच, चूहे, मक्खियां और अन्य कीड़े-मकोड़े देखे हैं।

इतने ही (45 प्रतिशत) लोगों ने शिकायत की कि खाना बनाते या परोसते समय शाकाहारी और मांसाहारी भोजन को अलग-अलग रखने के नियमों का पालन नहीं किया जाता। 40 प्रतिशत ग्राहकों को ऐसा खाना परोसा गया जो या तो बासी लग रहा था या उसे बार-बार गर्म किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, हर 10 में से 9 ग्राहकों ने पिछले 12 महीनों में कम से कम एक बार साफ-सफाई के नियमों का उल्लंघन होते हुए अपनी आंखों से देखा है।

बासी खाना और गंदे कुकिंग ऑयल ने बढ़ाई ग्राहकों की चिंता

जब ग्राहकों से पूछा गया कि उन्हें रेस्टोरेंट में सबसे ज्यादा डर या चिंता किस बात की सताती है, तो 79 प्रतिशत लोगों ने 'गंदे किचन, डाइनिंग एरिया और वॉशरूम' को अपनी सबसे बड़ी चिंता बताया। 74 प्रतिशत लोग इस बात से चिंतित थे कि रेस्टोरेंट में बासी या बचे हुए खाने का दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। 72 प्रतिशत ने कुकिंग ऑयल के बार-बार इस्तेमाल को खतरनाक माना।

63 प्रतिशत लोगों को एक्सपायर हो चुके या गलत तरीके से रखे गए कच्चे माल के इस्तेमाल का डर था। 61 प्रतिशत लोग कर्मचारियों की खराब पर्सनल हाइजीन और चूहों-कॉकरोच की मौजूदगी को लेकर परेशान दिखे। 60 प्रतिशत ने खराब प्लास्टिक के बर्तनों में खाना गर्म करने पर चिंता जताई, जबकि 47 प्रतिशत लोग शाकाहारी और मांसाहारी भोजन के एक साथ मिल जाने को लेकर फिक्रमंद थे।

महाराष्ट्र के नामचीन क्लबों पर कार्रवाई से सच हुए सर्वे के आंकड़े

लोकलसर्कल्स के इस सर्वे के नतीजे ऐसे समय में सामने आए हैं, जब महाराष्ट्र का खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) रेस्टोरेंट की साफ-सफाई को लेकर एक बड़ा अभियान चला रहा है। पिछले ही महीने महाराष्ट्र एफडीए ने अचानक किए गए निरीक्षण के बाद कई बड़े और प्रतिष्ठित क्लबों के फूड सेफ्टी (FSSAI) लाइसेंस निलंबित कर दिए थे। इनमें क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (CCI), विलिंगडन स्पोर्ट्स क्लब, एमआईजी क्रिकेट क्लब, आरके जुहू जिमखाना और अपर्णा जुहू जिमखाना जैसे बड़े नाम शामिल हैं।

नियम कड़े करने की उठी मांग

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अब ग्राहक भी फूड सेफ्टी विभागों से सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। सर्वे में 21,904 लोगों ने इस सवाल का जवाब दिया कि सरकार को क्या अनिवार्य करना चाहिए। इनमें से 74 प्रतिशत लोगों का स्पष्ट कहना है कि सभी रेस्टोरेंट और फूड डिलीवरी ऐप्स पर 'हाइजीन रेटिंग' (सफाई की रेटिंग) को सार्वजनिक तौर पर दिखाया जाना चाहिए। 72 प्रतिशत लोगों ने मांग की है कि हर तीन महीने में रेस्टोरेंट्स का निरीक्षण होना चाहिए।

ईरान ने फिर दिखाई ट्रंप को अकड़, कहा- अब आपके जाने के बाद ही होगी अमेरिका से बातचीत

वॉशिंगटन, एजेंसी। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लाख कोशिशों के बावजूद तेहरान वाशिंग्टन के सामने झुकने को तैयार नहीं। ट्रंप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने के लिए ईरान पर लगातार दबाव बना रहे हैं। इसी को लेकर अब ईरान ने ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि साल 2029 यानी जब तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त नहीं होता, तब तक वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खोलेगा।

ईरान ने सोमवार को ट्रंप प्रशासन के साथ किसी भी भविष्य की बातचीत से इनकार कर दिया है। ईरान ने साफ कहा है कि वह 20 जनवरी, 2029 को अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने

तक इंतजार करेगा। ईरान की इस बात से अमेरिका के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। ईरान का कहना है कि वो 2029 तक इंतजार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ट्रंप के सामने किसी भी कीमत पर झुककर कोई समझौता नहीं करेगा।

ईरानी मीडिया और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर गालिबाफ के सलाहकार माजिज शेकरी की ओर से किए गए एक बयान के मुताबिक, तेहरान अब ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने तक अपनी मौजूदा रणनीति जारी रखेगा। ट्रंप का मौजूदा कार्यकाल 20 जनवरी 2029 को खत्म होगा। इसके साथ ही ईरान ने अपनी 3 पुरानी शर्तें भी दोहराईं, जिससे ट्रंप प्रशासन मुश्किल में पड़ गया है ईरानी संसद अध्यक्ष गालिबाफ के वरिष्ठ सलाहकार माजिद शाकेरी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए तेहरान का रुख साफ किया। उन्होंने कहा, ट्रंप हमारे साथ किसी भी तरह के समझौते तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम 20 जनवरी 2029 तक इंतजार करेंगे और हम उनका कार्यकाल खत्म होने तक इसी तरह बने रहेंगे।

ईरान का रुख साफ

उन्होंने कहा कि ईरान का रास्ता न तो सीधी जंग है और न ही तत्काल समझौता, बल्कि ऐसी स्थिति बनाए रखना है जिसमें युद्ध भी न हो और शांति भी पूरी तरह स्थापित न हो। उन्होंने कहा कि इस माहौल में अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत की सार्वजनिक रूप से पुष्टि करना सरासर बेवकूफी होगी। उन्होंने कहा किअभी हमारे लिए सबसे बेहतरीन और जीतने वाली रणनीति यही है कि हम इनकार करें, अनिश्चितता बनाए रखें और रणनीतिक धैर्य दिखाएं।

ईरान ने रखी बड़ी शर्तें

ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत दोबारा शुरू करने के लिए अपनी कुछ प्रमुख शर्तें भी रखी हैं। इनमें करीब 300 अरब डॉलर के मुआवजे की मांग, जब्त की गई संपत्तियों की रिहाई और अमेरिकी सेनाओं की वापसी शामिल है। तेहरान का कहना है कि जब तक अमेरिका इन मांगों को स्वीकार नहीं करता, तब तक बातचीत आगे बढ़ाना संभव नहीं है। ईरान ने युद्ध के दौरान हुए नुकसान और कथित समझौते के उल्लंघन के लिए भी मुआवजे की मांग की है। तेहरान ने होर्मुज को फिर से खोलने को अपनी मांगों की स्वीकृति से जोड़ा है।

बातचीत नहीं, सिर्फ संदेशों का आदान-प्रदान

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने भी एक दिन पहले कहा था कि फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच कोई सीधी बातचीत नहीं चल रही है। हालांकि, दोनों देशों के बीच मध्यस्थों के जरिए संदेशों का आदान-प्रदान हो रहा है। अराग्ची के मुताबिक, कुछ देश दोनों पक्षों के बीच दोबारा बातचीत शुरू कराने के लिए माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ईरान का कहना है कि अमेरिका जब तक समझौते के उल्लंघन को रोकने और उसके नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार नहीं होता, तब तक औपचारिक बातचीत शुरू नहीं की जाएगी। बातचीत के साथ-साथ ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल स्ट्रेट ऑफ होर्मूज को लेकर भी अपना रुख सख्त रखा है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि अमेरिका की ओर से उसकी सभी शर्तें स्वीकार किए जाने तक स्ट्रेट ऑफ होर्मूज को नहीं खोला जाएगा।

यूक्रेन युद्ध का विरोध करने वाली पार्टी चुनाव से बाहर, रूसी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

मॉस्को, एजेंसी। रूस की सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि यूक्रेन में क्रेमलिन की सैन्य कार्रवाई का विरोध करने वाली एकमात्र पार्टी को अगले महीने होने वाले संसदीय चुनाव के लिए बैलेट (मतपत्र) से हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने क्रेमलिन-समर्थक पार्टी की अपील के बाद 'याब्लोको' जिसका रूसी में अर्थ 'सेब' है, का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। पिछले महीने, केंद्रीय चुनाव आयोग ने शुरू में याब्लोको को 10 अन्य पार्टियों के साथ बैलेट में शामिल होने की अनुमति दी थी।

कभी संसद में एक प्रमुख उदारवादी आवाज रही और अक्सर सरकार की आलोचना करने वाली याब्लोको ने बाद में स्टेट ड्यूमा में अपनी सीटों का ब्लॉक खो दिया, क्योंकि क्रेमलिन ने रूसी राजनीति पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। हाल के वर्षों में, याब्लोको एकमात्र ऐसी पंजीकृत विपक्षी पार्टी थी जिसने यूक्रेन में सेना भेजने का विरोध किया था। इसके चुनावी नारों में शामिल थे – 'युद्धविराम समझौते, कूटनीति और शांति के लिए!, 'हमारा लक्ष्य परमाणु युद्ध को रोकना है! और 'डर और राजनीतिक दमन से मुक्त रूस के लिए! 1990 के दशक में याब्लोको की सह-स्थापना करने वाले और इसकी राजनीतिक समिति के अध्यक्ष, अनुभवी उदारवादी राजनेता ग्रिगोरी यावलिंस्की ने इस फैसले की निंदा की और कहा कि पार्टी इसके खिलाफ अपील करेगी।

यावलिंस्की ने एक ऑनलाइन बयान में कहा, याब्लोको को चुनाव से बाहर करने का मतलब है उन लोगों के साथ बातचीत करने से इनकार करना जो ऐसे सवाल पूछते हैं जिनसे अधिकारी असहज महसूस करते हैं। हमें उम्मीद है कि अधिकारी शांति, स्वतंत्रता और बिना डर के जीवन की सार्वजनिक मांग पर ध्यान देंगे और अपनी नीति बदलेंगे। देश से बाहर रह रहे रूस के कई विपक्षी नेताओं ने वोटरों से याब्लोको का समर्थन करने की अपील की थी। इनमें क्रेमलिन के आलोचक एलेक्सी नवलनी की पत्नी यूलिया नवलनाया और नेता इल्या याशिन और व्लादिमीर कारा-मुर्ज़ा शामिल थे। नवलनाया ने 6 अगस्त को टेलीग्राम पर एक बयान में कहा, मेरा मानना है कि याब्लोको पार्टी का समर्थन करना नैतिक और राजनीतिक रूप से सही है। उन्होंने पार्टी के युद्ध-विरोधी रुख का जिक्र किया। सोमवार को कोर्ट में मौजूद याब्लोको के चेयरमैन निकोलाई रिबाकोव ने पार्टी को नवलनाया और विदेश में रह रहे क्रेमलिन के अन्य विरोधियों के उस समर्थन से अलग करने की कोशिश की, जिसे उन्होंने 'बिना वजह का समर्थन' बताया। ऐसा लगता है कि उन्होंने यह कोशिश इसलिए की ताकि पार्टी को बैलेट से हटाया न जाए। इस बीच, सोशल मीडिया पर याब्लोको के समर्थन में कई वीडियो छाए रहे। कई वीडियो में राजनीतिक नारे नहीं थे, बल्कि उनमें युवा लड़के-लड़कियां सेब पकड़े हुए दिखे- जब उनसे 18-20 सितंबर के चुनाव के लिए उनकी वोटिंग पसंद के बारे में पूछा गया- या फिर वे सेब का जिक्र करने वाले रूसी गानों पर नाचते हुए नज़र आए।

रूसियों को नाराजगी जाहिर करने का मिले मौका

रायबाकोव ने कोर्ट को बताया कि पार्टी इन वीडियो के लिए पैसे नहीं दे रही थी। उन्होंने कहा कि जो लोग इन्हें पोस्ट कर रहे थे, वे याब्लोको का समर्थन इसलिए कर रहे थे क्योंकि वे बस रूस में रहना चाहते हैं और मारे नहीं जाना चाहते। NEST सेंटर के सीनियर रिसर्च फेलो निकोलाई पेत्रोव ने कहा कि अधिकारियों ने शायद शुरू में याब्लोको को बैलेट पर रहने दिया ताकि रूसियों को अपनी नाराजगी जाहिर करने का मौका मिले और साथ ही यह भी दिखाया जा सके कि पार्टी को यूक्रेन पर अपने रुख के लिए बहुत कम लोगों का समर्थन मिलता है।

खाड़ी में नई टशन, ट्रंप ने ठुकराई ईरान की मांग, बोले- उसके हमले में मारे गए लोगों को मुआवजा दे तेहरान

वॉशिंगटन, एजेंसी। खाड़ी में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के खत्म होने के आसार नहीं दिख रहा है। होर्मुज को लेकर विवाद भी बना हुआ है। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल सोमवार को ईरान की उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें उसने अपने सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद हुए नुकसान के लिए भारी भरकम मुआवजे की मांग की थी। ट्रंप ने कहा कि इसके बजाय, ईरान को इन हमलों से हुई मौतों और घायलों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

ईरान, अमेरिका और इजराइल के हमलों से हुए नुकसान के लिए वाशिंगटन से 300 अरब डॉलर के मुआवजे की मांग कर रहा है। साथ ही वह 100 अरब डॉलर तक की फ्रीज की गई संपत्ति को भी रिलीज करने की मांग कर रहा है। यह उन कई शर्तों में से एक है जिन्हें तेहरान ने होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को फिर से खोलने की संभावना से जोड़ा है।

अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर कहा कि मुआवजे के लिए ईरान की मांग एक "दिलचस्प विचार" (Interesting Idea) है और उन्होंने कहा कि वह भी भविष्य की बातचीत में जवाबी मांग रखेंगे। उन्होंने कहा कि ईरानी प्रतिनिधि "पिछले 5 महीनों से जारी सैन्य अभियान" के दौरान हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह जंग इसलिए शुरू हुई क्योंकि ईरान परमाणु हथियार छोड़ने को ही तैयार नहीं था। इसके बाद अमेरिका-इजराइल ने 28 फरवरी को साझा सैन्य अभियान शुरू करते हुए ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दिया।

ट्रंप ने यह भी कहा कि मुआवजे में ईरान से जुड़े हमलों और संघर्षों में मारे गए या घायल हुए लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें 2000 में USS कोल पर बमबारी (USS Cole bombing) और कई अन्य घटनाएं शामिल हैं। उन्होंने ने कहा, "मैं भी ईरान से उन सभी लोगों के लिए मुआवजे की मांग कर रहा हूं जिन्हें उन्होंने मारा या फिर गंभीर रूप से घायल किया।"

अगली बातचीत में हम भी मांग करेंगे : ट्रंप

राष्ट्रपति ट्रंप ने खासतौर से ईरान के दिवंगत सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी का जिक्र किया और आरोप लगाया कि तेहरान उन संघर्षों में भी शामिल रहा है जिनकी वजह से हजारों लोगों की मौत हो गई। सुलेमानी की हत्या 2020 में बगदाद (इराक) में ट्रंप के आदेश पर किए गए एक टॉरगेटेड ड्रोन हमले में हुई थी। भविष्य की बातचीत में यह मांग शामिल होगी। ट्रंप ने उन प्रदर्शनकारियों के परिवारों के लिए भी मुआवजे की मांग की, जिनके बारे में उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 5 दशकों में ईरानी सरकार द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। उनका दावा है कि पिछले 5 महीनों में 52,000 लोग मारे गए हैं। ट्रंप ने कहा, "मैंने अपने प्रतिनिधियों को निर्देश दिया है कि वे भविष्य की किसी भी और सभी बातचीत में इस बात को मजबूती से रखें।"

पहले मुआवजा फिर होर्मुज पर बातचीत

समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान का कहना है कि रणनीतिक जलमार्ग को पूरी तरह से फिर से खोलने पर आपसी सहमति बनाने से पहले, अमेरिका को खाड़ी में जारी जंग से हुए नुकसान के लिए मुआवजा देने, प्रतिबंध हटाने, सैन्य धमकियां खत्म करने और ईरान की फ्रीज की गई संपत्ति जारी करने पर सहमत होना होगा। दूसरी ओर, 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' का कहना है कि रणनीतिक रूप से बेहद अहम इस जलमार्ग पर ईरान की स्थिति मजबूत है। और इस वजह से शिपिंग में बाधा डालने की ईरान की क्षमता ने ट्रंप के सामने विकल्पों को सीमित कर दिया है। बीच-बीच में होने वाले मिसाइल और ड्रोन हमलों ने यहां के कमर्शियल ट्रैफिक पर भी असर डाला है और ग्लोबल स्तर पर चिंता भी बढ़ा दी हैं।

... तब तक युद्ध का अखाड़ा बना रहेगा

ट्रंप ने बार-बार दावा किया कि होर्मुज स्ट्रेट खुला हुआ है, लेकिन इस रास्ते से शिपिंग गतिविधियां बुरी तरह बाधित होती रही हैं। इस वजह से उन्होंने ईरान को "बड़े पैमाने पर बमबारी अभियान" शुरू करने की धमकी भी दी। वहीं ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का कहना है कि होर्मुज तब तक बंद रहेगा जब तक वाशिंगटन की ओर से तेहरान की मांगों को स्वीकार नहीं कर लिया जाता। इन मांगों में युद्ध से हुए नुकसान का मुआवजा भी शामिल है। गार्ड्स ने यह भी कहा कि जब तक अमेरिका की ओर से ईरान की सभी शर्तें स्वीकार नहीं कर लिया जाता, तब तक यह स्ट्रेट "युद्ध का अखाड़ा" बना रहेगा।

छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में झारखंड बंद, सड़कों पर उतरी बीजेपी, कांग्रेस बोली- यह ड्रामेबाजी

झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची में JPSC-JSSC छात्रों का आंदोलन का दायरा बढ़ता जा रहा है। छात्रों के कल सोमवार को विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस एक्शन के विरोध में और छात्रों की मांगों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी (BJP) आज पूरे राज्य में बंद बुलाया है। बंद को देखते हुए रांची की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ऐहतियान स्कूल तक बंद कर दिए गए हैं।

बीजेपी की प्रदेश इकाई ने आज झारखंड बंद का आह्वान किया है। इसे देखते हुए रांची की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसी तरह के असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण के लिए जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे

लगाए गए हैं। साथ ही ड्रोन कैमरे की मदद से निगरानी की जाएगी। हालांकि बीजेपी ने अपने बंद में आवश्यक सेवाओं को अलग रखा है, यानी आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी।

मुख्य विपक्षी पार्टी का कहना है कि वह छात्रों के आंदोलन के समर्थन में सड़क पर उतर रही है और भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की जांच समेत छात्रों की मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाएगी। बंद को लेकर रांची समेत पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। राजधानी में पुलिस की अतिरिक्त तैनाती की गई है, जबकि कई निजी स्कूलों ने भी आज के बंद को देखते हुए छुट्टी कर दी है।

'झारखंड बंद' को लेकर झारखंड बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि आज का 'झारखंड बंद' ऐतिहासिक होगा। शांतिपूर्वक तरीके से विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर चार-चार बार किए लाठी चार्ज के विरोध में यह झारखंड बंद बुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग को मानना ही होगा। हेमंत सरकार को सीबीआई की जांच का आदेश देना ही होगा। उन्होंने कहा, "कांवरियों को और अन्य आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया है।"

बंद सुबह 8 बजे से मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा

इससे पहले बंद का आह्वान करते हुए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू ने कल रांची में पार्टी मुख्यालय में कहा कि यह बंद मंगलवार सुबह 8 बजे से मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा। उन्होंने कहा, "यह राज्यव्यापी बंद होगा। हालांकि, सभी आवश्यक सेवाओं को बंद के दायरे से बाहर रखा गया है।" कल विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच कई बार टकराव की स्थिति बनी। इस मामले में अधिकारियों ने बताया कि झारखंड विधानसभा के पास सोमवार को हुए टकराव में कई प्रदर्शनकारी और 4 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछार, आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज का सहारा लिया। यह टकराव प्रदर्शनकारियों के झारखंड विधानसभा के पास लगाए गए बैरेकेटिंग तोड़ने के बाद शुरू हुआ।

BJP की छात्रों को गुमराह करने की कोशिश : सोरेन

वहीं बीजेपी के झारखंड बंद का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्य विपक्षी पार्टी पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने बीजेपी नेताओं पर राजनीतिक लाभ के लिए आंदोलनकारी छात्रों को गुमराह करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। साथ ही सोरेन ने सोशल मीडिया के जरिए आंदोलनकारियों से बातचीत करने और विश्वास के जरिए अपनी समस्याओं का समाधान निकालने की अपील भी की। दूसरी ओर, कांग्रेस ने छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी के "झारखंड बंद " को सिर्फ राजनीतिक नौटंकी करार दिया। झारखंड कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस छात्रों के न्याय की लड़ाई को कमजोर नहीं होने देगी। उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों के साथ हुई घटना गंभीर है और यदि पुलिस द्वारा अनावश्यक बल प्रयोग किया गया है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी का अचानक बंद का ऐलान छात्रों के दर्द के प्रति संवेदना कम और राजनीतिक अवसरवाद ज्यादा दिखाई देता है।

झारखंड की भर्ती परीक्षाओं में हुई कथित अनियमितताओं को लेकर जारी आंदोलन आज मंगलवार को 18वें दिन में प्रवेश कर गया।

'आजकल ये एक पैटर्न बन गया है...' रणवीर सिंह के 'डॉन 3' छोड़ने पर फरहान अख्तर का बड़ा बयान, कही ये बात

रणवीर सिंह के 'डॉन 3' से बाहर होने के बाद बॉलीवुड में काफी विवाद हुआ था। अब फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर फरहान अख्तर ने इस पूरे मामले पर पहली बार ऐसा बयान दिया है, जिसे रणवीर सिंह पर तंज माना जा रहा है।

फरहान अख्तर और रणवीर सिंह के बीच 'डॉन 3' को लेकर विवाद अब भी चर्चा में है। इसी बीच फरहान ने एक इंटरव्यू के दौरान रणवीर का नाम लिए बिना उनके फिल्म छोड़ने को लेकर ऐसी बात कह दी, जो अब सुर्खियों में आ गया है।

फरहान अख्तर हाल ही में अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म 'दिल चाहता है' के 25 साल पूरे होने के मौके पर 'द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया' से बातचीत कर रहे थे। इस बीच उन्होंने रणवीर सिंह के 'डॉन 3' छोड़ने का जिक्र किया। रणवीर का नाम लिए बिना फरहान ने कहा, 'शूटिंग से एक महीने पहले फिल्म छोड़ दी... जो आजकल एक पैटर्न बन गया है।'

आखिर क्या है रणवीर के 'डॉन 3' छोड़ने का पूरा मामला?

बता दें कि रणवीर सिंह ने 'डॉन 3' की शूटिंग शुरू होने से कुछ दिन पहले फिल्म से बाहर होने का फैसला किया था। इसके बाद फिल्म को लेकर काफी विवाद हुआ।

कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि रणवीर इस बात से नाराज थे कि फरहान अख्तर ने उनकी जानकारी के बिना इस रोल के लिए ऋतिक रोशन से संपर्क किया था। हालांकि, फरहान ने इन दावों को खारिज किया था।

वहीं, रणवीर के फिल्म छोड़ने के बाद उनके द्वारा साइनिंग अमाउंट वापस करने की पेशकश की खबरें सामने आई थीं। दूसरी तरफ मेकर्स ने फिल्म के प्री-प्रोडक्शन में हुए नुकसान के लिए करीब 45 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की थी।

FWICE ने रणवीर के खिलाफ लिया था फैसला

इस मामले में फरहान अख्तर ने FWICE से भी संपर्क किया था।

इसके बाद फिल्म संस्था ने रणवीर सिंह के खिलाफ नॉन-कोऑपरेशन का फैसला लिया था।

हालांकि, बाद में इस निर्देश को वापस ले लिया गया।

संस्था ने यह भी साफ किया था कि रणवीर सिंह को बैन नहीं किया गया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणवीर ने भी इस मामले में फिल्म संस्था को कानूनी नोटिस भेजा था।

रणवीर ने इस पूरे विवाद पर ज्यादा खुलकर बात नहीं की और उनकी तरफ से उनके प्रवक्ता के जरिए ही जानकारी सामने आती रही।

'मेरी इज्जत और ईमानदारी मेरे लिए बहुत जरूरी', CINTAA विवाद पर बोलीं पूनम ढिल्लों, आरोपों पर कही बड़ी बात

बीते दिनों CINTAA के 8 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उपासना सिंह ने वीडियो जारी कर इस बात की जानकारी दी थी और पूनम ढिल्लों और पद्मिनी पर गंभीर आरोप लगाए थे। अब पूनम ने सदस्यों के इस्तीफे, CAWT को लेकर मतभेद और अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों पर भी बात की।

पूनम ढिल्लों ने ANI से बातचीत में कहा कि विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब कुछ लोगों को कानूनी प्रक्रिया के जरिए वह नतीजा नहीं मिला, जिसकी उन्हें उम्मीद थी। इसके बाद उन्होंने CINTAA के सदस्यों पर दबाव बनाने और गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए।

पूनम ने कहा कि उनके और एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरे के खिलाफ जिस तरह की बातें कही गईं, वे बेहद दुखद और आपत्तिजनक थीं। उन्होंने कहा कि दोनों ने शुरुआत में इन आरोपों का जवाब नहीं देने का फैसला किया था।

उन्होंने कहा, 'जब चीजें उनके मुताबिक नहीं हुईं तो उन्होंने CINTAA के सदस्यों को CAWT के जरिए अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की। जब ऐसा नहीं हो पाया तो हमारे खिलाफ अजीब और गंभीर आरोप लगाए जाने लगे।'

पूनम के मुताबिक, उनके खिलाफ इतनी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया कि वह चाहतीं तो मानहानि की कानूनी कार्रवाई भी कर सकती थीं। उन्होंने कहा कि कई आपत्तिजनक मैसेज और बयान बड़े लेवल पर फैलाए गए।

पूनम ढिल्लों ने कहा कि उन्होंने और पद्मिनी कोल्हापुरे ने वर्षों की मेहनत से अपनी पहचान और सम्मान बनाया है। वह किसी भी कीमत पर अपनी इज्जत से समझौता नहीं करेंगी।

उन्होंने कहा, 'मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी इंटीग्रिटी बहुत जरूरी है। हमने जो कुछ कमाया है, वह एक-दो साल में नहीं कमाया। हमने दशकों में अपनी पहचान और सम्मान बनाया है। अपने व्यवहार, गरिमा और लोगों के साथ रिश्तों के जरिए हमने यह मुकाम हासिल किया है।'

उन्होंने आगे कहा कि CINTAA के सदस्यों के हित में काम करना ही उनका मकसद रहा है और वह अपनी प्रतिष्ठा को किसी भी विवाद की वजह से खराब नहीं होने देंगी।

कई बार मन हुआ CINTAA की EC छोड़ दूं

पूनम ढिल्लों ने इससे पहले एक वीडियो मैसेज के जरिए भी इस पूरे विवाद पर अपनी बात रखी थी।

उन्होंने बताया कि शुरुआत में उन्होंने चुप रहने का फैसला किया था, लेकिन व्हाट्सएप पर चल रहे मैसेज और वॉइस नोट्स देखने के बाद उन्हें सामने आकर बोलना पड़ा।

उन्होंने कहा कि वह पिछले करीब डेढ़ साल में कई बार CINTAA की एक्जीक्यूटिव कमिटी छोड़ने के बारे में सोच चुकी थीं, क्योंकि हर पहल और हर काम का विरोध किया जा रहा था।

पूनम ने कहा, 'हम लोग इंडस्ट्री में 42, 45 या 48 साल से हैं। क्या आपको सच में लगता है कि इतने समय के बाद हम इस तरह की बेवफाई करेंगे?

पिछले एक-डेढ़ साल में कई बार मेरा मन हुआ कि मैं CINTAA की EC छोड़कर चली जाऊं।

इन लोगों ने हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल बना दी थी। हर चीज का विरोध और हर पहल का विरोध।'

व्हाट्सएप पर मैसेज और वॉइस नोट्स पर भी जताई नाराजगी

पूनम ने दावा किया कि कुछ CINTAA सदस्यों के जरिए उनके खिलाफ बेहद अपमानजनक मैसेज और वॉइस नोट्स भी शेयर किए गए। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने ये मैसेज देखे और सुने होंगे। उन्होंने कहा कि अगर उन मैसेज को देखकर CINTAA के सदस्यों को तकलीफ हुई होगी, तो सोचिए उन्हें खुद कितना बुरा लगा होगा। पूनम ने कहा, 'मैं इंडस्ट्री में 45 साल से ज्यादा समय से हूं। इतने वर्षों में मैंने अपनी इज्जत और अपना नाम कमाया है। बाकी सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन इज्जत मेरे लिए बहुत जरूरी है।'

CINTAA के आठ सदस्यों ने इस्तीफा दिया है।

इन इस्तीफों को CINTAA की जनरल सेक्रेटरी उपासना सिंह को सौंपा गया है।

इस्तीफा देने वालों में हेमंत पांडे, मुकेश ऋषि, साहिला चड्ढा, हेता परमार, पुनीत इस्सर, विंदू दारा सिंह, विकास वर्मा और दीपक पाराशर शामिल हैं।

वामिका गब्बी– लोकेश कनगराज की डीसी का दूसरे दिन धमाल, किया इतना कलेक्शन

फिल्म डीसी 7 अगस्त को रिलीज हुई। फैंस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन फिल्म की कमाई में इजाफा हुआ। वामिका और लोकेश की जोड़ी को पसंद किया जा रहा है। आइए जानते हैं फिल्म ने दो दिन में कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया।

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने शनिवार को 6.70 करोड़ की कमाई की है। फिल्म को 3,549 शोज मिले। फिल्म को 35.7 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली। फिल्म ने दूसरे दिन हिंदी में 40 लाख कमाए। वहीं तमिल भाषा में 4.55 करोड़ की कमाई की। तेलुगू में फिल्म ने 1.75 करोड़ का कलेक्शन किया।

फिल्म ने पहले दिन 4.40 करोड़ का बिजनेस किया। फिल्म को 3,504 शोज मिले। वहीं फिल्म को 24।8 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली।

वहीं फिल्म ने दूसरे दिन ओवरसीज मार्केट में 3 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने ग्रॉस 5.25 करोड़ का बिजनेस किया। वर्ल्डवाइड फिल्म ने 17.99 करोड़ का बिजनेस किया।

फिल्म को अरुण माथेस्वरन ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में पॉपुलर डायरेक्टर लोकेश कनगराज लीड रोल में हैं। एक्टर के तौर पर ये उनका डेब्यू है। डेब्यू फिल्म से वो छा गए हैं। डीसी की कहानी फिल्म देवदास की तर्ज पर है। ये रोमांटिक एक्शन थ्रिलर है। फिल्म में लोकेश देवदास और वामिका चंद्रा के रोल में हैं। फिल्म में कस्तूरी राजा सेंदूरन के रोल में हैं। वहीं थलाइवासल विजय अरासू के रोल में हैं।

लोकेश के वर्कफ्रंट पर नजर डालें तो 2016 में उन्होंने डायरेक्टर-राइटर के तौर पर जर्नी की शुरुआत की थी। उन्होंने 2016 में फिल्म अवियल को डायरेक्ट किया था। फिर उन्होंने 2017 में फिल्म मानगरम को डायरेक्ट किया। 2019 में उनकी फिल्म कैथी आई। 2021 में उन्होंने मास्टर, 2022 में विक्रम, 2023 में माइकल, लियो, फाइट क्लब फिल्में डायरेक्ट की। 2025 में उनकी कुली आई। 2026 में फिल्म 29 आई, इसे उन्होंने प्रोड्यूस किया।

उनकी एक्टिंग की बात करें तो फिल्म मास्टर में उन्होंने कैमियो किया। इसके अलावा वो सिंगापुर सैलून, कट्टलन और जन नायकन में कैमियो रोल में दिखें। अब 2026 में लीड रोल में फिल्म डीसी से डेब्यू किया।

वहीं एक्ट्रेस वामिका गब्बी की बात करें तो उन्होंने फिल्म जब वी मेट से डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में सपोर्टिंग रोल, बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम किया। 2013 में उन्होंने फिल्म सिक्सटीन से लीड के तौर पर डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने पंजाब, तेलुगू, मलयालम,तमिल, तेलुगू फिल्मों में काम किया। अब वो इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हो रही हैं। उनके पास कई सारी बड़ी फिल्में हैं।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित।
शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com